दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का
RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003
www.citydarpan.com

अम्बाला छावनी इंडस्ट्रियल एरिया के पम्प हाउस को बिजली की हॉटलाइन से जोड़ने की मंजूरी मिली : अनिल विज

टांगरी नदी को गहरा करने के लिए अब 15 नवंबर से पुन: मिट्टी/सिल्ट निकालने का कार्य प्रारंभ होगा

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी इंडस्ट्रियल एरिया के पंप हाउस को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पंप हाउस को हॉटलाइन से जोड़ने के लिए मंजूरी मिल गई है और जल्द ही पंप हाउस को हॉटलाइन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, आगामी 15 नवंबर से टांगरी नदी में मिटटी/सिल्ट इत्यादि की निकालने का कार्य आरंभ किया जाएगा।

श्री विज आज अम्बाला छावनी में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया की दीवार बनाने के कार्य का टेंडर हाई पॉवर परचेस कमेटी की बैठक में पारित किया जाएगा और उसके पश्चात दीवार निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा ताकि इंडस्ट्रियल एरिया का पानी से बचाव किया जा सके।

बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को टांगरी नदी में मिट्टी/सिल्ट निकालने का कार्य 15 नवंबर तक प्रारंभ करने के निर्देश दिए। नदी को चंदपुरा से लेकर कोटकछुआ तक गहरा किया जाएगा जिससे बरसाती पानी की निकासी और बेहतर होगी। उन्होंने टांगरी नदी पर तीन स्थानों पर काजवे निर्माण का कार्य भी जल्द प्रारंभ कर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, श्री विज द्वारा संबंधित अधिकारियों को रामगढ़ माजरा गांव से टांगरी नदी में पानी लिफ्ट करने हेतु पंप लगाने के भी निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि नदी को गहरा करने का कार्य इसी वर्ष प्रारंभ कर दिया गया था, मगर बरसातों की वजह से इसे बीच में ही रोकना पड़ा था।

बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने शहीदी स्मारक में निर्माण कार्य को एक नवंबर तक पूरा करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दिए तथा शेष कार्य जल्द पूरा करने को भी कहा। उन्होंने शहीदी स्मारक के कार्य से संबंधित जानकारी अधिकारियों से ली। साइंस म्यूजिक के संबंध में अधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज को बताया कि साइंस म्यूजियम का टेंडर शुक्रवार 17 अक्टूबर को अलॉट होगा जिसके बाद इसके निर्माण का कार्य आरंभ किया जाएगा। मंत्री अनिल विज ने मच्छौंडा आरओबी निर्माण कार्य प्रारंभ करने के साथ-साथ टांगरी नदी बांध रोड का निर्माण कार्य भी जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद को महेशनगर में बब्याल रोड के शेष हिस्से पर सीवरेज जल्द से जल्द डालने के निर्देश दिए ताकि शेष रोड का निर्माण पूरा किया जा सके।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी शहरी क्षेत्र से डेयरियों को बाहर करने के लिए ब्राह्मण माजरा में डेयरी काम्पलेक्स का कार्य जल्द प्रारंभ करने के निर्देश नगर परिषद अधिकारियों को दिए। इसके अलावा, उन्होंने मल्टीलेवल पार्किंग में लिफ्ट लगाने के कार्य को जल्द पूरा करने, दीवाली से पहले खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने, स्टेडियम के समक्ष फुटबाल चौक का निर्माण कार्य प्रारंभ करने, बस क्यू शेल्टरों का निर्माण करने के साथ-साथ पंखे लगाने की मजबूत व्यवस्था करने, उगाड़ा-बाड़ा में खाली भूमि पर गौशाला स्थापित करने व अन्य दिशा-निर्देश दिए।

इसी प्रकार, ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने विद्युत निगम के अधिकारियों को सड़कों से ट्रांसफार्मर हटाने, सदर बाजार में अंडरग्राउंड बिजली की खराब तारों को आधुनिक मशीन के माध्यम से बदलने, टांगरी बांध रोड से 11 केवी लाइन के पोल शिफट करने एवं अन्य दिशा-निर्देश दिए।

हरियाणा में अधिकारी-कर्मचारियों की विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में नए दिशा-निर्देश जारी

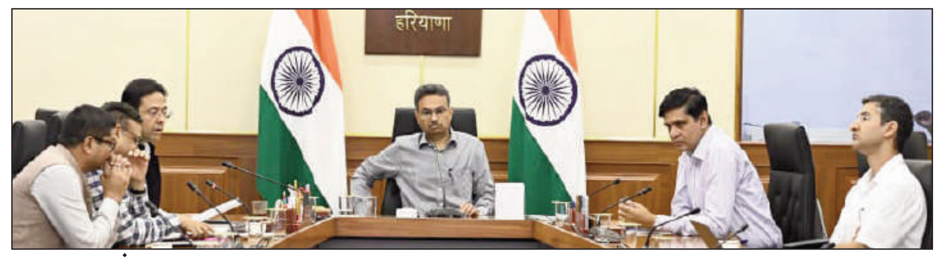

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के वित्त विभाग ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और पूर्व में सभी आदेशों को निरस्त समझा जाएगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा जारी ये दिशा-निर्देश ग्रुप "ए", "बी", "सी" एवं "डी" के सरकारी कर्मचारियों के साथ ही हरियाणा से जुड़े अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होंगे। वित्त विभाग (एफ.आर. शाखा) इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग की सिफारिश पर अनुमोदन प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की विदेश यात्राओं के संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हालांकि अब वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। सरकारी खर्च पर की जाने वाली आधिकारिक विदेश यात्राओं के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक आधिकारिक और एक निजी यात्रा की अनुमति दी जाएगी। दोनों यात्राओं की कुल अवधि तीन सप्ताह से अधिक नहीं होगी। प्रस्तावों को संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित "चेक-लिस्ट" के साथ मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर वित्त विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेश यात्रा भत्ता हेतु बजट का पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है। व्यक्तिगत कारणों से स्वयं के व्यय पर विदेश यात्रा के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक निजी यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इस स्थिति में उस देश का नाम अनुमोदन पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा, जहां की यात्रा की जानी है। यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध अपराध से जुड़ा कोई मामला लंबित है या मुख्य दंड हेतु आरोपपत्र जारी किया गया है, तो ऐसे मामलों में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि निजी यात्रा का खर्च विभाग से जुड़ी किसी निजी संस्था द्वारा वहन किया जा रहा है तो अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में विदेश यात्रा के लिए एक्स-पोस्ट फैक्टो अप्रूवल प्रदान नहीं की जाएगी। बिना पूर्व अनुमति के विदेश जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नायब सैनी वर्तमान हरियाणा सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर पंचकूला में राज्य स्तरीय समारोह में करेंगे शिरकत

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में वर्तमान राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, पहलों और जनकल्याण को प्रतिबद्ध रोडमैप को सांझा करेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज उच्च स्तरीय बैठक कर समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। जिला उपायुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।

मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रमों को लेकर सभी तैयारियां समयबद्ध और समन्वित तरीके से की जाएं। पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का लाइव प्रसारण सभी जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम के दौरान पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को विकास अनुदान ग्रांट वितरित करेंगे और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 (चरण-क्क) के अंतर्गत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन पत्र सौंपेंगे। मुख्य सचिव ने राज्य और जिला स्तर पर सुचारू व्यवस्था, व्यापक जनभागीदारी और सरकार की उपलब्धियों का समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभागों को सुरक्षा, जन-सम्पर्क और जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं के लिए प्रभावी समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए।

संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल में दिवाली मेले का किया भव्य आयोजन

अनिल गोयल
लाडवा

संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल, लाडवा में बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ दिवाली मेला का आयोजन किया गया। पूरा विद्यालय दीपों, लाइटों और रंगोली से जगमगा उठा था।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, आपसी सौहार्द और सामाजिक एकता की भावना को प्रबल करना था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन सैनी, उपाध्यक्ष, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, जबकि इस अवसर पर शिव गुप्ता, मंडल अध्यक्ष, भाजपा, श्रीमती साक्षी खुराना प्रधान, लाडवा नगरपालिका तथा अमन सिंगला की गरिमामयी उपस्थिति भी रही।

कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. रणमीत बत्रा मैनेजिंग ट्रस्टी ने की। उनके साथ मंच पर प्राचार्या श्रीमती अमरजीत कौर संधू, महोदया हरनूप मास्टर, तविष, राजिंदर चावला, इंदर सिंह मल्होत्रा, तेजिंदर पाल सिंह ढिल्लो और सरबजीत सिंह गुग्लानी भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन सैनी ने कहा –यह मेरे लिए अत्यंत खुशी और गर्व की बात है कि मुझे आज उस विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है जिसकी स्थापना महान संत पंडित संत निश्चल सिंह जी महाराज के कर-कमलों द्वारा हुई थी। उन्होंने विद्यालय के पूर्व छात्रों – अंबर गर्ग, निशांत सिंघल, खुशबू, शुभम, पलक बठला (एम.बी.बी.एस., एम.डी.), सुनेना (विंग कमांडर, गुजरात), शिवराज ढिल्लो (डी.एस.पी., पटियाला) – की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय के कराटे खिलाड़ी अब जापान में अपनी प्रतिभा दिखाने जा रहे हैं और हाल ही में मन्नतप्रीत ने दसवीं कक्षा में 500 में से 498 अंक प्राप्त कर जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधक डॉ. बरयाम सिंह, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. रणजीत बत्रा, तथा प्राचार्या श्रीमती अमरजीत कौर संधू की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन सभी के अथक प्रयासों से विद्यालय निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर है।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने कव्वाली, लोकगीत और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में प्रस्तुत किया गया पंजाबी भांगड़ा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। अंत में प्राचार्या अमरजीत कौर संधू ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का धन्यवाद किया तथा आगामी त्योहारों के लिए शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि दीपों का यह पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है और हमें सदा सत्य, सेवा व स्नेह के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। पूरे विद्यालय में उल्लास, उमंग और दीपों की रौशनी से भरा वातावरण लंबे समय तक सबके मन में बस गया।

संक्षिप्त-समाचार

कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने 28 सरकारी स्कूलों के बच्चों संग मनाई दीपावली

चंडीगढ़। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने दिवाली पर इस बार खास पहल शुरू की है।उन्होंने फरीदाबाद जिले के 28 सरकारी स्कूलों के हजारों बच्चों को 15 हजार देसी घी के लड्डू वितरित कर खुशियों की सौगात दी। इस अवसर पर श्री विपुल गोयल ने कहा कि त्योहारों का असली अर्थ तभी है, जब समाज के हर वर्ग के साथ खुशियां बांटी जाएं। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, और उनकी मुस्कान ही सबसे बड़ा उत्सव है। उन्होंने कामना की कि आने वाला दिवाली का त्योहार प्रदेश व देश के लोगों के जीवन में खुशियाँ ले कर आए। कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का है और इस सपने को पूरा करने में बच्चे भविष्य के भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बच्चों को शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि भारत का विकास उनके प्रयासों से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि सेवा, सहयोग और सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों की शिक्षा और पोषण के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन समाज की भागीदारी से यह अभियान और मजबूत होगा। उन्होंने शिक्षकों से भी अपील की कि वे बच्चों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा की भावना को बढ़ावा दें। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने स्वच्छ दिवाली, हरित दिवाली का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने सभी को दीवाली की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों के साथ दीपक भी जलाए। इस पहल की अभिभावकों ने सराहना की और कहा कि श्री विपुल गोयल का यह कदम बच्चों में आत्मविश्वास और अपनत्व की भावना बढ़ाने वाला है। वहीं शिक्षकों ने कहा कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सरकारी स्कूल के बच्चों की यह दिवाली यादगार बना दी।

बच्चों संग दीपावली मना कर समाजसेवी निधि मोहन ने पेश की मिसाल

पुण्डरी। भाजपा महिला मोर्चा जिला सचिव समाजसेवी निधि मोहन ने पूंडरी के सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों के साथ दीपावली मनाई और इस त्यौहार को वास्तव में खुशियों का त्यौहार बना दिया। कार्यक्रम की शुरूआत में निधि मोहन ने बच्चों से संवाद करते हुए दीपावली का महत्व बताया और उनसे हिंदू त्योहारों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका बच्चों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। इसके बाद उन्होंने बच्चों को दीये, पेंटिंग कलर्स और मिठाइयाँ वितरित कीं। कार्यक्रम में लगभग 150 से अधिक बच्चों ने दीयों को रंगों से सजाया और अपनी कला से सुंदर डिजाइन बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान स्कूल परिसर बच्चों की रचनात्मकता और मुस्कुराहट से जगमगा उठा। निधि मोहन ने कहा कि त्यौहार की रौशनी तब और ज्यादा जगमगाती है, जब हम उसे किसी जरूरतमंद के साथ साझा करते हैं। दीपावली सिर्फ अपने घर में नहीं, समाज के हर कोने में मनाई जानी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को फल और मिठाइयाँ वितरित की गईं। इस अनोखे आयोजन से बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान सबके दिल को छू गई। विद्यालय की प्रिंसिपल व स्टाफ ने निधि मोहन का आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे सामाजिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करते हैं।

सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को प्राइवेट आयुष अस्पतालों में भी दी जा रही है ईलाज की सुविधा : आरती राव सिंह

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों/पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के ईलाज के लिए काफी सुविधाएं दे रही है। सरकारी अस्पतालों के अलावा कई प्राइवेट अस्पतालों को भी इम्पैनल्ड किया है ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी अस्पताल में ईलाज करवा सकें। कर्मचारियों की मांग पर प्रदेश सरकार ने कई प्राइवेट आयुष अस्पतालों को भी इम्पैनल्ड किया है।इस दिशा में कदम उठाते हुए विभाग ने दो और आयुष अस्पतालों को इम्पैनल्ड कर दिया है जिससे संख्या बढ़कर अब करीब एक दर्जन हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से झज्जर जिला में आयुष अस्पताल संस्कारम हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर , खेड़ी तालुका , पटौदा तथा हिसार जिला के बरवाला में

स्थित वेदामृता हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को इम्पैनल्ड किया है। हरियाणा के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स तथा उनके आश्रित अब इन प्राइवेट आयुष अस्पतालों में भी ईलाज करवा सकेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित बीमारियों की जांच एवं ईलाज करवा कर इन अस्पतालों के मेडिकल बिल पास करवा सकेंगे। हरियाणा आयुष निदेशालय के प्रवक्ता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इन इम्पैनल्ड प्राइवेट आयुष अस्पताल के स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी किसी भी शिकायत के मामले में आयुष विभाग से संपर्क करेगा। उन्होंने इम्पैनल्ड अस्पतालों की शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी अस्पतालों में किसी भी आपात स्थिति/आपदा/मरीजों की अधिकता की स्थिति में इम्पैनल्ड अस्पताल आवश्यकतानुसार अपनी एम्बुलेंस, आईसीयू, बर्न यूनिट, वार्ड बेड आदि साझा करने के लिए सहमत होंगे। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी वैधानिक नियमों/दिशानिदेशों/ अधिनियमों/ अधिसूचनाओं का इम्पैनल्ड प्राइवेट आयुष अस्पताल द्वारा पालन किया जाएगा। उपर्युक्त एनएबीएच मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक अस्पताल मान्यता प्रमाणपत्र की वैधता के अधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए इम्पैनल्ड रहेगा। इसके बाद, अस्पताल को नए सिरे से आवेदन करना होगा।

मिठाई विक्रेता मिठाई बनाने तथा भंडारण पर रखें विशेष ध्यान : डॉक्टर कृष्णकांत

संवाददाता
लाडवा

डॉक्टर कृष्णकांत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाडवा की अध्यक्षता में लाडवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की गई । छापेमारी के दौरान मिठाइयों के बनाने तथा भंडारण इत्यादि का निरीक्षण किया गया ।निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ दुकानों पर मिठाइयों का भंडारण उचित नहीं था । मिठाइयों में मक्खियों मच्छर इत्यादि गिरे हुए थे तथा उन को ढककर नहीं रखा गया था ।जिनको मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वह मिठाइयां इत्यादि को भंडारण के लिए सही तरीके से ढक कर रखें तथा उचित सामग्री को ही उपयोग में लाएं। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आम जनता की सेहत से खिलवाड़ ना करें तथा आम जनता को बीमारी से रोकने में

स्वास्थ्य विभाग का संपूर्ण सहयोग दें । डॉक्टर कृष्णकांत ने बताया कि इस तरह का निरीक्षण समय-समय पर किया जाता रहेगा तथा आज जो भी मिठाई विक्रेता संदिग्ध पाए गए उनको भविष्य में इस प्रकार का कार्य न करवाने बारे चेतावनी दी गई व खराब सामान को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया और उनको कहा गया कि अगर भविष्य में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

आम जनता को बेहतर स्वच्छ तथा शुद्ध मिठाई मिल सके इस कड़ी में डॉक्टर कृष्णकांत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाडवा ने 13 अक्टूबर को शहर लाडवा के सभी मिठाई विक्रेताओं की मीटिंग ली थी। जिसमें उन्हें उचित रखरखाव तथा मिलावटी तथा अशुद्ध मिठाई ना बेचने बारे निर्देश भी दिए थे। मिलावटी और नकली मिठाई की पहचान के बारे में डॉक्टर कृष्णकांत ने बताया कि कुछ सरल तरीकों से मिलावटी वाली नकली मिठाई की पहचान की जा सकती है जैसे कि त्यौहारों में रंग-बिरंगी मिठाईयां बिकती हैं। ऐसे में इनमें हानिकारक कलर मिलाए जाते है। ऐसे में आप रंग वाली मिठाईयों को खरीदने से बचे। अगर आप फिर भी रंग-बिरंगी मिठाईयां ले रहे है तो उसका एक पीस अपने हाथ में ले और चेक करें। अगर आपके हाथ में कलर लग रहा है तो समझ जाइए मिठाई में काफी ज्यादा कलर मिक्स किया गया है।

नव नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों को वेतन का मामला, सरकार ने लिया संज्ञान, जल्द हो भुगतान

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को कॉमन कैडर के अंतर्गत नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों का वेतन समय पर जारी करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। ये कर्मचारी विज्ञापन संख्या 01/2023 के माध्यम से चयनित हुए थे, जिन्होंने 28 अगस्त, 2025 या उसके बाद विभिन्न विभागों में कार्यभार ग्रहण किया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया गया है कि 28 अगस्त, 2025 के नियुक्ति आदेशों के अनुसार विभिन्न विभागों में ज्वाइन करने वाले कुछ नव नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित वेतन उनकी जॉइनिंग की वास्तविक तिथि से तत्काल जारी किए जाएं, ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी न हो। गौरतलब है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन कर्मचारियों की अनुशंसा 2 जुलाई, 2025 को की गई थी, जिसके पश्चात उन्हें विभिन्न विभागों में कॉमन कैडर के अंतर्गत नियुक्त किया गया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि वेतन बिल तैयार करने की प्रक्रिया में देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर नव-नियुक्त कर्मचारियों के हित प्रभावित होते हैं।

मुख्य सचिव ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने कर्मचारियों का ब्यौरा एचआरएमएस पोर्टल पर शीघ्र दर्ज करें, क्योंकि ई-बिलिंग प्रणाली वेतन बिल तैयार करने के लिए इन्हीं आंकड़ों पर निर्भर करती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से संबंधित मामलों में सरकार ने स्पष्ट किया है कि पी.आर.ए.एन. जारी किए बिना केवल दो माह का वेतन ही जारी किया जा सकता है। इसके बाद वेतन जारी के लिए पी.आर.ए.एन. अनिवार्य है।

छठ पूजा से पहले यमुना की स्वच्छता का संकल्प, हरियाणा सरकार ने तेज की तैयारियां

संवाददाता
चंडीगढ़

आगामी छठ पूजा पर्व के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने यमुना नदी की स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागों के बीच समन्वय को और प्रभावी बनाने, प्रदूषण नियंत्रण के कठोर उपाय लागू करने और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यमुना और उसकी सहायक नदियों के तटों पर पूजा-अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

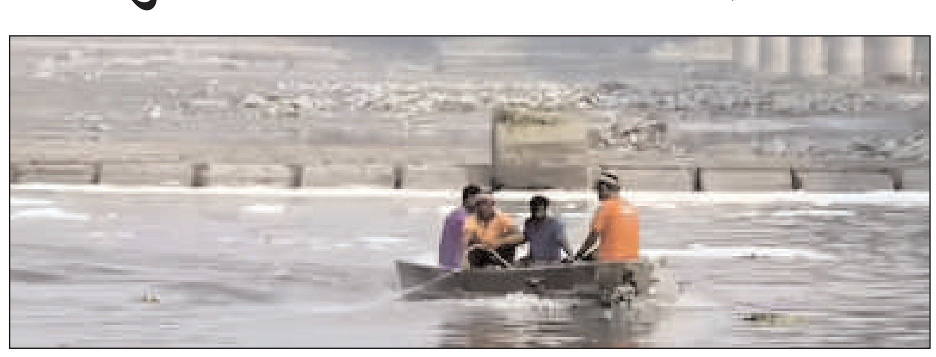

मुख्य सचिव ने यमुना कैचमेंट एरिया में स्थित सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एस.टी.पी.) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सी.ई.टी.पी.) की 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यकारी अभियंताओं को 28 अक्तूबर, 2025 तक इन प्लांट्स के संचालन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के आदेश दिए ताकि कोई भी खराबी आने पर इसे तुरन्त ठीक किया जा सके और सभी संयंत्र निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप कार्य करें। इसकी निरंतर निगरानी के लिए कनिष्ठ अभियंता और उपमंडल अभियंताओं को तैनात किया गया है, जबकि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड गठित कर आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निमार्णाधीन और कार्यरत, सभी संयंत्रों की सूची तैयार कर आगामी कार्ययोजना बनाई जाए और परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित की जाए।

श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राज्य सरकार यमुना को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ नदी प्रणाली न केवल पर्यावरणीय आवश्यकता है, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी भी है। छठ पूजा इस दिशा में सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने का उपयुक्त अवसर है।

मुख्य सचिव ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए कि वे उन औद्योगिक इकाइयों की पहचान करें जिनसे नदी या उसके सहायक नालों में प्रदूषक उत्सर्जित होने की संभावना है। साथ ही, उनके संचालन पर भी कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने यह भी कहा कि परिचालन या मॉनिटरिंग डेटा में किसी भी प्रकार की हेराफेरी पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग और सिंचाई विभाग छठ पूजा के दौरान नदी तटों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नालों और नदी किनारों से ठोस अपशिष्ट की तुरंत सफाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा, नगर निगमों को पर्याप्त जनशक्ति और मशीनरी तैनात करने को कहा गया है ताकि छठ पर्व के दौरान घाटों और नदी तटों की सफाई और सुगम पहुँच सुनिश्चित हो सके। अगले 15 दिनों तक पुलिस, नगर निगम, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा एक संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के सीवेज या टैंकर अपशिष्ट को अवैध रूप से यमुना में डाले जाने से रोका जा सके। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि उपलब्ध क्षमता अनुसार टैंकरों के माध्यम से सीवेज उठाकर उपचार के लिए एस.टी.पी. तक पहुँचाया जाए। संबंधित उपायुक्त और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इस कार्य की निगरानी करेंगे। यमुना और उसकी सहायक नदियों की सुरक्षा के लिए प्रदेशभर में 364 पुलों पर बाड़ लगाने (फेंसिंग) का कार्य किया जा रहा है। इनमें सर्वाधिक स्थल सिरसा (74), कुरुक्षेत्र (73), चरखी दादरी (50) और कैथल (37) जिलों में हैं।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का

नवोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक भुपेंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेंजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1 सेक्टर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित- 160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का
RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003
www.citydarpan.com

11 साल घणा कमाल
11 साल, तरक्की बेमिसाल

हरियाणा सरकार

म्हारा हरियाणा नॉन-स्टॉप हरियाणा

संकल्प से सिद्धि की राह में हरियाणा सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्व जनकल्याण हेतु लिए गए 217 संकल्पों में से पूरे किए गए 46 संकल्प। शेष सभी संकल्पों को जल्द पूर्ण करने हेतु कार्य प्रगति पर।

मुख्य संकल्प

महिला

1. हरियाणा की पात्र महिलाओं को **दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना** के तहत **प्रतिमाह 2,100 रुपये** की वित्तीय सहायता।
2. **हर घर–हर गृहिणी योजना** के तहत अंत्योदय तथा बी.पी.एल. परिवारों को केवल **500 रुपये में एल.पी.जी. सिलेंडर** दिया जा रहा है।

युवा

3. नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 24,000 **युवाओं को ग्रुप–सी की सरकारी नौकरियां** दी।
4. ग्रुप–सी के पदों के लिए जुलाई, 2025 में लगभग 13.50 **लाख युवाओं ने सी.ई.टी. परीक्षा** दी।
5. शहीद सैनिकों के हर बच्चे को **6वीं से 12वीं कक्षा** तक 60,000 **रुपये**, **स्नातक** तक 72,000 **रुपये** तथा **स्नातकोत्तर** तक 96,000 **रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति** का प्रावधान।
6. **डंकी रूट की समस्या** को जड़ से खत्म करने के लिए कानून लागू।

किसान

7. **नकली खाद, बीज और कीटनाशक** बनाने व बेचने वालों को **5 साल की सजा** का कानून लागू।
8. सभी 24 **फसलों** की न्यूनतम समर्थन मूल्य **(MSP)** पर खरीद।
9. किसानों को 48 **घंटे** में डी.बी.टी. के माध्यम से **फसल का भुगतान** किया जा रहा है।

गरीब

10. सभी जिला **सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों** में किडनी रोगियों के लिए **मुफ्त डायलिसिस** सेवा शुरू।
11. ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 20 **वर्षों से अधिक समय** से काबिज सभी परिवारों को भूमि का **मालिकाना हक** दिया।
12. **आयुष्मान भारत योजना** के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को **5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज** की सुविधा।

सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा के WhatsApp चैनल से जुड़ने के लिए क्यू आर कोड स्कैन करें

सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

www.prharyana.gov.in | Follow us on @dipprharyana

संपादकीय

दूध नहीं, जहर खा रहे हैं आप! यूरिया और टिनोपाल से बन रहा नकली पनीर

त्योहारों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए दुकानों पर सफेद और चमकदार पनीर के ढेर दिखते हैं। लेकिन अब यही 'चमक' खतरे की घंटी बन गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की हालिया जांचों में खुलासा हुआ है कि कई जिलों में यूरिया, डिटर्जेंट और टिनोपाल जैसे रसायनों की मदद से नकली पनीर तैयार किया जा रहा है, जो सेहत के लिए गंभीर खतरा है। अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर बरामद किया गया। अधिकारियों के अनुसार, कुछ गोदामों में दूध का एक बूँद भी नहीं था–फिर भी पनीर के ब्लॉक तैयार किए जा रहे थे। यह पनीर यूरिया, वनस्पति तेल, स्टार्च, डिटर्जेंट पाउडर और टिनोपल मिलाकर तैयार किया जा रहा था। नोएडा, मेरठ, आगरा, लखनऊ और बरेली में छापों के दौरान कई टन नकली पनीर जब्त किया गया। वहीं, गोरखपुर और कानपुर में ऐसे कारखाने पकड़े गए जहाँ रातों-रात तैयार पनीर को पैक करके बाजार में भेजा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि ये नकली डेयरी नेटवर्क खास तौर पर त्योहारों के सीजन में सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान मांग बढ़ने से दूध और असली पनीर की कीमतें ऊपर जाती हैं। इससे मुनाफाखोर तत्व नकली सामग्री से सस्ता पनीर बनाकर बाजार में उतार देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह नकली पनीर बनाने की प्रक्रिया बहुत सुनियोजित और वैज्ञानिक दिखने वाली होती है। इसमें असली दूध का इस्तेमाल न के बराबर होता है। पहला चरणः पानी में पाम ऑयल, हाइड्रोजनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल या सस्ता डीजल ऑयल जैसे पदार्थ मिलाए जाते हैं। दूसरा चरणः यूरिया, स्टार्च, और कैल्शियम पाउडर डालकर मिश्रण को गाढ़ा किया जाता है ताकि वह दूध जैसा दिखे। तीसरा चरणः इस मिश्रण में डिटर्जेंट या सर्फेक्टेंट डालकर झाग और गाढ़ापन बनाया जाता है। चौथा चरणः टिनोपल या ब्लू (जो आमतौर पर कपड़ों को चमकाने के लिए इस्तेमाल होता है) मिलाकर पनीर को सफेद और आकर्षक बनाया जाता है। पाँचवाँ चरणः मिश्रण को ठंडे मोल्ड में डालकर जमाया जाता है और फिर उसे बाजार में असली पनीर बताकर बेचा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले अधिकांश पदार्थ औद्योगिक हैं और मानव सेवन के लिए खतरनाक माने जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यूरिया और डिटर्जेंट जैसे रासायनिक तत्व शरीर में जहर की तरह काम करते हैं। यूरिया, जो सामान्यतः खेतों में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, शरीर के किडनी और लिवर पर अत्यधिक दबाव डालता है। टिनोपल एक ऑप्टिकल ब्राइटनर है जो खाने योग्य नहीं होता। इसका उपयोग कपड़े, पेपर और डिटर्जेंट उद्योग में किया जाता है। इसके सेवन से पेट दर्द, उल्टी, एलर्जी, त्वचा रोग, श्वसन संबंधी दिक्कतें और लंबे समय में कैंसर तक का खतरा बढ़ सकता है। लखनऊ स्थित एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. निखिल अग्रवाल के अनुसार, 'नकली पनीर का नियमित सेवन शरीर में धीमे जहर की तरह काम करता है। यह बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकता है, बुजुर्गों में लीवर और किडनी की कार्यक्षमता को कम कर सकता है और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से खतरनाक है।' खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्यों को निर्देश दिया है कि त्योहारों के दौरान दूध, मिठाई और पनीर की जांच तेज की जाए। नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में संदिग्ध डेयरी इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ जिलों में 20 से अधिक फैक्ट्रियों को सील किया गया है और हजारों किलो मिलावटी पनीर नष्ट किया गया। साथ ही, अपराधियों पर 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006' की धारा 59 और 63 के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें तीन साल तक की सजा और लाखों रुपये का जुमार्ना हो सकता है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि टीमों को रैंडम सैंपलिंग और मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए जांच का आदेश दिया गया है। साथ ही, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सावधान किया जा रहा है कि वे पनीर की असामान्य सफेदी या अजीब गंध को गंभीरता से लें। विशेषज्ञों ने कुछ आसान घरेलू तरीके बताए हैं जिनसे उपभोक्ता नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं–पानी में गर्म करें: असली पनीर गर्म पानी में डालने पर मुलायम रहता है, जबकि नकली पनीर टूट जाता है या तैलीय झिल्ली छोड़ता है। गंध जांचेंः असली पनीर में हल्की दूधिया गंध होती है। नकली पनीर में रासायनिक या साबुन जैसी गंध महसूस होती है। टेक्सचर जांचेंः असली पनीर काटने पर हल्का ग्रेन्यूलर (दानेदार) होता है जबकि नकली पनीर रबर जैसा होता है। जलाने पर परीक्षणः नकली पनीर जलाने पर साबुन जैसी गंध आती है, क्योंकि उसमें फैट और डिटर्जेंट मिलाया गया होता है। सरकारी कार्रवाई के साथ-साथ जनता की सतर्कता भी जरूरी है। उपभोक्ता अगर संदिग्ध पनीर या डेयरी उत्पाद देखें तो तुरंत फूड सेफ्टी हेल्पलाइन (1800-11-2100) या स्थानीय विभाग को शिकायत दर्ज कराएं। नकली पनीर बेचने वालों के खिलाफ सामुदायिक निगरानी से भी इस पर रोक लगाई जा सकती है। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, 'मिलावट सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, बल्कि नैतिक अपराध भी है।' इसका सीधा असर छोटे किसानों और असली डेयरी उत्पादकों की आमदनी पर पड़ता है। जब नकली उत्पाद सस्ते दामों पर बाजार में आते हैं, तो असली उत्पादक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। अंत में कह सकते हैं कि त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन यह समस्या मौसमी नहीं बल्कि प्रणालीगत है। जरूरत है कि दूध और डेयरी उत्पादों की सप्लाई चेन को डिजिटली ट्रैक किया जाए। सेहत की रक्षा के लिए हर घर को मिलावट के खिलाफ सजग रहना होगा।

केबीसी के चर्चित बच्चा प्रकरण से उपजे बड़े सवाल

आयुषी दवे (हि.स)

भारत के बेहद लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का एक चर्चित एपीसोड काफी सुर्खियों में है। इसमें बच्चे का अति आत्मविश्वास शुरू में तो सबको खूब भाया लेकिन शो आगे बढ़ने के साथ, जवाब देने के उसके तरीके ने सबको हैरान किया। बच्चों के एक एपीसोड में 10 साल के बच्चे ने अमिताभ बच्चन को नियम समझाने और विकल्प न बताने की न केवल हिदायत दी बल्कि अपनी अति आत्मविश्वासी छवि पेश कर कुछ देर के लिए बोलती भी बंद कर दी हालांकि थोड़े ही सवालों के बाद वह खेल से बाहर हो गया लेकिन बच्चा जितनी देर रहा, कई अनसुलझे सवालों को छोड़ गया। शो को नियमित देखने वालों और इस बारे में सुनने वालों में इसकी काफी चर्चा है कुछ इसे बच्चे के अहम तो कुछ शिष्टाचार से जोड़कर देखते हैं। तमाम तरह की आलोचनाओं के बावजूद बच्चे के समर्थन में भी कुछ सामने आए। हालांकि कई का यह भी मानना है कि ऐसे एपीसोड केबीसी को नहीं दिखाना था। टीआरपी और प्रतिस्पर्धा की होड़ में एक्सीडेण्टली बैठे-बिठाए हाथ आए ऐसे मामले भला प्रसारण कंपनी क्यों छोड़े? निश्चित रूप से बच्चे के प्रति तरह-तरह के कमेण्टस आने का सिलसिला जल्द थमने वाला नहीं। लेकिन विचारणनीय यह है कि इसका बच्चे की मनःस्थिति पर कैसा और कितना गहरा असर पड़ेगा? संभव है कि जल्द इस पर डिबेट्स का दौर भी शुरू हो जाए।

गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर बच्चे ने ऐसा व्यव्हार क्यों किया? शो के दौरान बीच-बीच में बच्चे के जवाब देने के अनुचित तरीके से उसके माता-पिता भी असहज दिखे। ऐसा लगा कि ऐसी वातार्लाप बच्चे की दिनचर्या का अंग ही है। बच्चे के लिए भले यह नया न हो और आम हो लेकिन क्या यह सही है? इस पर मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों का ध्यान स्वाभाविक है। इस तरह की प्रवृत्ति कैसे रुके, गहन मंथन का विषय है। टीवी में ऐसे कार्यक्रम आएं न आएं यह नियामकों का जिम्मा है। लेकिन दस साल के बच्चे के व्यव्हार से ढेरों सवाल जरूर उठ खड़े हुए हैं।

आज की आपाधापी और भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को अभिभावक कितना वक्त दे पाते हैं? वो संस्कार कहां गुम हो गए जिसके लिए भारत दुनिया में जाना जाता है? पश्चिमी सभ्यता इतना सर चढ़ बोल रही है कि पहले फटी जींस और अब फटे शर्ट की फैशन हमारी आत्ममुग्धता है? बच्चों का बदलता व्यवहार, उनमें रूखापन और अतिविश्वास क्यों है? इस पर मनोविज्ञानिकों की राय को भी देखना होगा जो बताते हैं कि ऐसे व्यव्हार का कारण कहीं ना कहीं बच्चे का विकासात्मक असंतुलन है। जिस बच्चे को लेकर यह शुरूआत हुई है वह जेन अल्फा से ताल्लुक रखता है। यह सबसे तेज और सबसे हाईटेक पीढ़ी मानी जाती है। 2010 से 2024 के बीच पैदा यह, वह पहली पीढ़ी है जो पूरी तरह से 21वीं सदी में जन्मी है। जन्म से ही तकनीक, स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ पले-बढ़े ये बच्चे पूरी तरह डिजिटल और साइबर परिवेश में रहते हैं। यही नए डिजिटल युग के असल प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। तेजी और हाजिरजवाबी इनकी पहचान है। इनके लिए, सबकुछ तुरंत होता है जैसे जवाब, खेल, प्रशंसा और ध्यान।

ऐसी प्रवृत्ति के भयावह दुष्परिणामों के बारे में सोचे बिना हम अपनी पीढ़ी को कहां ले जा रहे हैं? इस पर कौन सोचेगा? क्या हम, आप इस गति या तेजी की कीमत समझते हैं? उनके मस्तिष्क का फ्रंटल लोब, जो निर्णय लेने, धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण के लिए ज़िम्मेदार है, बहुत धीमा विकसित हो रहा है। इनमें एक स्पष्ट पैटर्न दिखता है। इनमें विचारों में तेजी तो काम पर नियंत्रण कम रहता है। इनके व्यव्हार से मस्तिष्क का असंतुलन भी झलकता है। इसे तंत्रिका-विकासात्मक विकार कहते हैं जो ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अतिसक्रियता और आवेग जैसी समस्याओं का कारण बनता है। यह मस्तिष्क की वह स्थिति है जो बच्चों और किशोरों में उनके स्कूल, घर, रिश्तों में दैनिक कामकाज को प्रभावित कर सकती है। यह वयस्कता तक बनी रहती है। इसे एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं।

वहीं, यह एक तरह का ओडीडी यानी ऑप्जिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर है। यह भी व्यवहार संबंधी विकार है जिससे बच्चों में लगातार अवज्ञाकारी, असहयोगी और शत्रुतापूर्ण व्यवहार झलकता है। बच्चे दूसरों के साथ बहस करते हैं, नियमों का पालन करने से इनकार करते हैं और चिड़चिड़े होते हैं। यदि यह व्यवहार लंबे समय तक बना रहता है, तो यह रिश्तों और दैनिक जीवन को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। दूसरों से बात करते समय बीच में बोलना या बीच में ही टोक देना, बेचैनी और इंतजार करने में असमर्थता, अतिसक्रियता, आवेग में आकर जवाब देना, अधिकार प्राप्त लोगों से बहस करना या उनका विरोध करना, जिद और मैं हमेशा सही हूँ- वाला रवैया अपनाना, गलत होने पर भी गलतियाँ न मानना वो लक्षण हैं जो भावनात्मक असंतुलन दशार्ते हैं। ऐसी स्थितियों में भावनाएँ मस्तिष्क को नियंत्रित करती हैं, न कि मस्तिष्क भावनाओं को। इसमें बुद्धिमान दिखने खातिर आंतरिक दबाव और अपने डर को प्रभुत्व या आज्ञाकारी लहजे से छुपा लेना ठीक नहीं होता।

केबीसी के जिस एपीसोड से यह मुद्दा गमार्या, उसमें बच्चा कहता है कि अगर मैं कम से कम 12 लाख नहीं जीता तो मुझे बताया गया कि आपके साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता! यह कहना बेहतर प्रदर्शन के लिए उस पर दबाव और चिंता को बताता है। कहने की जरूरत नहीं कि वजह माता-पिता या सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़ा दबाव है। अहम यह कि माता-पिता अपने बच्चे की बुद्धिमत्ता और जीत की तारीफ तो करते हैं लेकिन उसकी भावनाओं को नहीं समझते, शांत या धैर्यवान होना नहीं सिखाते।

वास्तव में आपाधापी और प्रतिस्पर्धा में रात-दिन लगे माता-पिता भी तो उसी दौड़ में शामिल हैं जिसमें बच्चा है। भला क्या और क्या उम्मीद की जाए? समय से पहले गैर जरूरी मामलों में बच्चों की संलिप्तता और इसके लिए मददगार डिजिटल संसाधन पकड़ाना कितना उचित है? यह सवाल शुरूआत से बहस में रहा लेकिन सवाल वही कि क्या हम वक्त से पहले अपने बच्चों को बिना सोचे, समझे बड़ा कर रहे हैं?

बचपना, मिट्टी में खेलने की आजादी, गांव-गलियां, गिल्ली डण्डा, गेड़ी चलना, लंगड़ी कूद, बोरा कूद, लुका-छिपी और तमाम पुराने पारंपिक खेल गायब होते जा रहे हैं। सबका स्थान मोबाइल और गेमिंग ने लेकर बच्चों को समय से पहले बड़ा और बूढ़ा जरूर बना दिया है। कितना अच्छा होता कि समय रहते ऐसी उच्छृंखलता रोक पाते? क्या फिर लौट पाएगा बच्चा, बचपन और अनुशासन और बच्चों का झुण्ड, आंगन में किलकारी, दौड़ना, कूदना, लड़ना और एक हो जाना! शायद लंबा इंतजार करना होगा, कितना? यह तो किसी को नहीं पता।

(लेखिका, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन्स में इंजीनियर हैं।)

वर्दी में डकैत

प्रमोद भार्गव (हि.स)

अभी तक मध्य प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार से अर्जित काली कमाई के अनगिनत मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन अब वर्दी पहने पुलिस वालों ने सिवनी के हवाला कारोबारियों से 2.96 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूटने के बाद परस्पर बांट लिए। इस लूट में महिला एसडीओपी पूजा पांडेय, एसआई अर्पित भैरम समेत 11 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस मामले में पुलिसकर्मियों के विरुद्ध डकैती, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो गई है।

रक्षक से भक्षक बने उच्च शिक्षित नौकरशाहों की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, एक पखवाड़े के भीतर समाज को झकझोर देने वाली ऐसी तीन और घटनाएं सामने आई हैं। राजधानी भोपाल में दो आरक्षकों ने उदित गायकी की पीट-पीट कर हत्या कर दी। बालाघाट थाने के मालखाने से प्रभारी ने 75 लाख रुपए की जब्त सामग्री गायब कर दी। कदाचर से जुड़ा एक मामला लोकायुक्त पुलिस के छापे से सामने आया है। दो माह पहले सेवानिवृत्त हुए आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया से एक करोड़ की नगदी के साथ 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई है। वैसे तो यह हाल लगभग पूरे देश में है, लेकिन मप्र में देश भक्ति-जनसेवा के नाम पर जैसी लूटमार, हिंसा और अराजकता लगातार देखने में आ रही है, वैसे उदाहरण अन्य प्रदेशों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये मामले नौकरशाही में अवमूल्यन के प्रतीक बनने के साथ समाज की चिंता बढ़ाने वाले है। क्योंकि जब पुलिस ही अपने दायित्व से भटक रही है, तब पीड़ित जनता की सुरक्षा का दायित्व किस पर है?

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्य मंत्री परिषद ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के नजरिये से विशेष अदालतें गठित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी। इन अदालतों में उन लोकसेवक राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध मामले चलाने की शुरूआत हुई थी, जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। इस दायरे में सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री और भृत्य से लेकर प्रमुख सचिव के साथ सेवानिवृत्त अधिकारियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों व मंत्रियों को भी जांच के दायरे में ले लिया गया था। अदालतों को एक साल के भीतर मामला निपटाना जरूरी था। इस फैसले की अपील उच्च न्यायालय में करने का प्रावधान है। लोक सेवक ने आय से अधिक संपत्ति गलत तरीकों से हासिल की है तो सरकार तत्काल प्रभाव से इस जायदाद को अस्थाई तौर से जब्त करेगी और प्रकरण में दोषी पाए जाने पर सरकार का संपत्ति पर अधिकार स्थाई हो जाएगा। लेकिन यह कानून कागजी और व्यवस्था आखिरकार सफेद हाथी साबित हो रही है। इस विधेयक में दावा तो यह किया गया था कि कदाचर से जुड़े ऐसे मामले एक साल के भीतर अंजाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा इक्का-दुक्का मामलों में ही देखने में आया। नतीजतन परिणाम ढांक के तीन पात रहा।

प्रजातांत्रिक मूल्यों में नौकरशाही का भ्रष्टाचार और अब सार्वजनिक डकैती के मामले राष्ट्रघाती हैं। यह सामाजिक सद्भाव को तो खंडित करता ही है, संस्थागत संरचना के प्रति अविश्वास भी पैदा करता है। लोकतांत्रिक और आर्थिक प्रक्रिया में बहुसंख्यक लोगों की भागीदारी भ्रष्टाचार के चलते वंचित रह जाती है। संसाधनों के आबंटन में अनियमितता बरती जाती है, नतीजतन गरीब, वंचित, व सीमांत तबके के हित प्रभावित होते हैं। सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक विषमता का आधार भी भ्रष्टाचार बन रहा है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बड़ा खतरा है। 1993 के मुंबई विस्फोट में जो हथियार प्रयोग में लाए गए थे, वे उस तस्करी का परिणाम थे जो भ्रष्टतंत्र के बूते फलीभूत हुई थी। ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था जिस देश में सम्मान व प्रतिष्ठा की सूचक बन गई हो उस देश की लोकतंत्रीय प्रणाली और संप्रभुता कब तक कायम बनी रह पाएगी? यह सवाल भी एक आम भारतीय को कचोटता है।

दरअसल लोकतंत्र की उम्र बढ़ने के साथ-साथ भ्रष्ट-तंत्र लगातार मजबूत होता रहा है। यही कारण है कि हमारे देश में जनकल्याणकारी योजनाएं आम-जन की हित पोषक साबित होने की बजाय अब तक सरकारी अमले के लिए रिश्वत का चमत्कारी तिलिस्म सिद्ध होती रही हैं। 'ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया सेंटर फार मीडिया स्टडीज' ने जो अध्ययन किया है, वह बताता है एक साल के भीतर हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मूलभूत अनिवार्य व जनकल्याणकारी सेवाओं को हासिल करने के लिए तकरीबन कई हजार करोड़ रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। यह सांस्कृतिक रूप से सभ्य, मानसिक रुप से धार्मिक और भावनात्मक रूप से कमोवेश संवेदनशील समाज के लिए सिर पीट लेने वाली बात है। इस अध्ययन ने प्रकारांतर से यह तय कर दिया है कि हमारे यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी, मध्याह्न भोजन, पोलियो उन्मूलन के साथ स्वास्थ्य लाभ व भोजन के अधिकार संबंधी योजनाएं किस हद तक जमीनी स्तर पर लूट व भ्रष्टाचार की हिस्सा बनी हुई हैं।

यही कारण है कि प्रशासनिक पारदर्शिता के जितने भी उपाय एक कारगर औजार के रूप में उठाए गए वे सब के सब प्रशासन की देहरी पर जाकर ठिठक जाते हैं।

ई-प्रशासन के बहाने कम्प्यूटर का अंतर्जाल सरकारी दफ्तरों में इसलिए फैलाया गया था कि यह प्रणाली भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगाएगी ही ऑनलाइन के जरिये समस्याओं का समाधान भी तुरंत होगा। लेकिन इस नेटवर्किंग में करोड़ों रुपये खर्च कर दिये जाने के बावजूद इसी प्रणाली के जरिए भ्रष्टाचार का दायरा और बढ़ गया है। न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों और पुलिस का वही परंपरागत ढर्रा जस की तस कायम है, जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के समय से बरकरार है। फाइलों का निराकरण आज भी कछुए की गति से चल रहा है। कंप्यूटर सरकारी क्षेत्र में टाइपराइटर का उम्दा विकल्प भर बनकर रह गया है।

सूचना के अधिकार को भ्रष्टाचार से मुक्ति का पर्याय माना जा रहा था। क्योंकि इसके जरिये आम नागरिक हरेक सरकारी विभाग के कामकाज व नोटशीट पर अधिकारी की दर्ज टिप्पणी का लेखा-जोखा तलब कर सकता है। लेकिन सरकारी अमले की अनियमितताएं घटने की बजाए और बढ़ गईं। भ्रष्टाचार पर किए अध्ययन इसका उदाहरण है। इससे जाहिर होता है कि सूचना का अधिकार भी भ्रष्टाचार से मुक्ति की कसौटी पर खरा नहीं उतरा? ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे जो श्रम कानून हैं वे इस हद तक प्रशासनिक तंत्र के रक्षा कवच बने हुए हैं कि वे पारदर्शिता और जवाबदेही की कोई भी शर्त स्वीकारने को मजबूर नहीं होते?

दरअसल, हमने औपनिवेशिक जमाने की नौकरशाही को स्वतंत्र भारत में जस की तस मंजूर लेने की एक बड़ी भूल की थी। नतीजतन आज भी हमारे लोकसेवक उन्हीं दमनकारी परंपराओं से आचरण ग्रहण करने में लगे हैं, जो अंग्रेजी राज में विद्रोहियों के दमन की दृष्टि से जरूरी हुआ करती थीं। इस सिलसिले में नौकरशाहों के लिए ढाल बनी संविधान के अनुच्छेद 310 एवं 311 में बदलाव की वकालत अर्से से हो रही है। लेकिन इनमें बदलाव की हिम्मत नरेन्द्र मोदी भी नहीं कर पाए हैं। भ्रष्टाचार समाप्त करने में यही अनुच्छेद रोड़े अटका रहे हैं। लिहाजा लोकसेवक से जुड़ी सेवा शर्तों को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है।

म.प्र. सरकार ने विधेयक के मसौदे में संविधान के अनुच्छेद 310 एवं 311 को संसद में बदले बिना प्रदेश सरकार कैसे भ्रष्ट संपत्ति को जब्त करेगी इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं। क्योंकि इन अनुच्छेदों में निर्धारित प्रावधानों के चलते ही ताकतवर नेता और प्रशासक जांच एजेंसियों को प्रभावित तो करते ही हैं, तथ्यों व साक्ष्यों को भी कमजोर करते हैं। भ्रष्टाचार के ज्यादातर मामलों में सीबीआई भी भरोसेमंद व मजबूत गवाहों की तुलना में संख्या की दृष्टि से ज्यादा गवाहों को तरजीह देती है। फलस्वरूप मामला लंबा खिंचता है और गवाहों के बयानों में विरोधाभास पैदा होता है, जिसका लाभ भ्रष्टाचारी को मिलता है। इसके वनस्बित मामले से सीधे जुड़े इक्का-दुक्का गवाहों को ही तरजीह देना चाहिए। इन सक्षम व चश्मदीद गवाहों के बयान ही गुनाह को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में दस्तावेज ही पर्याप्त सबूत होते हैं। बहरहाल, प्रशासनिक सुधार किए बिना क्रांतिकारी बदलाव लाना असंभव है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आज का राशिफल

मेषः आज आपका दिन संतुलित और योजनाबद्ध रहेगा। पारिवारिक कलह समाप्त होगा और मन में शांति लौटेगी, हालांकि कुछ अनजानी चिंताएँ मन को विचलित कर सकती हैं। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ के संकेत हैं। नौकरी की तलाश करने वालों को नया अवसर मिल सकता है।

वृषभः पहले किया गया निवेश लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी योग्यता और मेहनत की सराहना होगी। दांपत्य जीवन में निकटता और सामंजस्य बढ़ेगा। अविवाहित जातकों के लिए प्रेम संबंध बनने के योग हैं। संतान की उपलब्धियों से गर्व और प्रसन्नता मिलेगी।

मिथुनः आज कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बना रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, परंतु बढ़ते खर्चों से थोड़ी चिंता हो सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने शब्दों में संयम रखना होगा।

कर्कः रुके हुए कार्य दोबारा शुरू होंगे। शारीरिक थकावट या दर्द की समस्या रह सकती है। माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी, जबकि ससुराल पक्ष से धन लाभ के संकेत हैं। अत्यधिक जोश में नया कार्य आरंभ करने से बचें।

सिंहः कार्यस्थल पर चुनौतीपूर्ण माहौल का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से तालमेल बनाए रखें। अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करें। प्रेम संबंधों में मतभेद या गलतफहमी हो सकती है। वाणी में कठोरता से बचें।

कन्याः मानसिक दबाव और थकान महसूस हो सकती है। ससुराल पक्ष में कोई समस्या उभर सकती है। निर्णय लेने में भ्रम रह सकता है। सिरदर्द या माइग्रेन से राहत के लिए दिनचर्या और खानपान का विशेष ध्यान रखें।

तुलाः नई आय के स्रोत मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें। सामाजिक कार्यों में सहभागिता बढ़ेगी। प्रियजनों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत करेंगे।

वृश्चिकः आज आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और वरिष्ठ अधिकारी संतुष्ट रहेंगे। धन की कमी से रुके कार्य फिर शुरू हो सकते हैं। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। अपनी गलतियों से सीख लेने का दिन है। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा।

धनुः सहकर्मियों की आलोचना झेलनी पड़ सकती है। जीवनसाथी से मतभेद संभव हैं। गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, क्योंकि यह पेट या पीठ दर्द का कारण बन सकता है। संयमित दिनचर्या अपनाना लाभदायक रहेगा।

मकरः अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें। विज्ञान, तकनीक या नवाचार के प्रति आकर्षण रहेगा। घर में मन विचलित हो सकता है, यात्रा योग बन रहे हैं। धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है। आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें।

कुंभः आज का दिन अनुकूल रहेगा। कार्यस्थल पर सहयोगियों का समर्थन मिलेगा और आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। बच्चे अनुशासित रहेंगे। रिश्तेदारों से मिलना-जुलना होगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। पुरानी बीमारी थोड़ी परेशानी दे सकती है।

मीनः समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। पिताजी से महत्वपूर्ण चर्चा संभव है। अतिउत्साह में कोई निर्णय न लें, अन्यथा काम बिगड़ सकता है। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी, परंतु विरोधी सक्रिय रहेंगे।

मंदिर का धन देवता का, सरकार का नहीं; हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला और धर्मनिरपेक्षता की सच्ची कसौटी

डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हि.स)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का हालिया फैसला जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 'मंदिर का धन देवता का है, सरकार का नहीं।' वस्तुतः न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने अपने 38 पन्नों के विस्तृत निर्णय में मंदिरों की दान राशि के उपयोग पर सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि मंदिरों में आने वाला हर चढ़ावा देवी-देवताओं का है और इसका उपयोग धार्मिक, धर्मार्थ और सामाजिक उत्थान से जुड़े कार्यों में ही किया जा सकता है। देखा जाए तो इस निर्णय ने हिमाचल प्रदेश के साथ पूरे देश में एक पुराने और उपेक्षित प्रश्न को पुनः जीवित कर दिया है, जब मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों की आय में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो हिंदू मंदिरों की निधि पर सरकारी नियंत्रण क्यों?

भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, परंतु व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कई बार 'हिंदू धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण' बनकर रह गया है। देश के कई राज्यों में मंदिर 'देवस्थान विभागों' द्वारा संचालित होते हैं, जहाँ मंदिरों की दान राशि का उपयोग लोक कल्याण योजनाओं या प्रशासनिक कार्यों में नाम पर किया जाता है। वहीं मस्जिदों की संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन, चर्च की संपत्ति चर्च ट्रस्टों के अधीन और गुरुद्वारों की निधि स्वयंभू प्रबंधक समितियों के नियंत्रण में रहती है। हिन्दू धर्म को छोड़कर ऐसा ही अन्य रिलीजन का हाल है।

प्रश्न यह है कि क्या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही होना चाहिए कि राज्य हिंदू संस्थानों को 'रेगुलेट' करे और अन्य धर्मों की संस्थाओं को 'स्वायत्तता' दे? हिमाचल हाईकोर्ट ने इसी विषमता को रेखांकित करते हुए कहा कि 'मंदिरों में आने वाला दान श्रद्धालुओं का भगवान पर विश्वास है, उसे राज्य के राजस्व की तरह उपयोग करना अनुचित है और यह आस्था के साथ विश्वासघात है।' हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 'देवता एक विधिक इकाई (juristic person) हैं और मंदिर की निधि उसी देवता की संपत्ति है।' सरकार या मंदिर अधिकारी उसके संरक्षक मात्र हैं। यदि कोई ट्रस्टी मंदिर निधि का दुरुपयोग करता है, तो यह आपराधिक विश्वासघात (criminal breach of trust) माना जाएगा।

अदालत ने आदेश दिया कि सभी मंदिर ट्रस्ट अपनी मासिक आय-व्यय रिपोर्ट, ऑडिट सारांश और दान का ब्यौरा सार्वजनिक करें, ताकि भक्तों का विश्वास बना रहे और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।

निर्णय में अदालत ने मंदिर निधियों के उपयोग की सीमाएँ भी तय कीं – यह राशि देवी-देवताओं की देखभाल, मंदिरों के रखरखाव और सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार में उपयोग होगी। इसके अतिरिक्त, इसका उपयोग गुरुकुलों की स्थापना, गोशालाओं के संचालन, पुजारियों के प्रशिक्षण, यज्ञशालाओं के निर्माण, अस्पृश्यता मिटाने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने जैसे धर्मार्थ कार्यों में किया जा सकेगा। दअदालत ने सख्ती से कहा कि मंदिर निधियों का उपयोग सरकारी योजनाओं, सड़कों-पुलों के निर्माण, निजी व्यवसायों, होटलों या मॉल संचालन, या मंदिर अधिकारियों के निजी लाभ के लिए नहीं किया जा सकता।

अब देखा जाए तो यह प्रश्न नया नहीं है। 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने 'श्री लक्ष्मिंदर थिरुमलाई देवस्वामिगल बनाम कमिश्नर, हिंदू रिलीजीयस एंडोमेंट' मामले में कहा था कि 'मंदिर एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था है और देवता उसकी विधिक इकाई हैं।' 1983 में तमिलनाडु हाईकोर्ट ने कहा था कि 'राज्य मंदिर निधियों को अपने राजकोष में शामिल नहीं कर सकता क्योंकि वे धार्मिक उद्देश्य के लिए प्राप्त होती हैं।' 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला ट्रस्ट से जुड़े आदेशों में दोहराया कि 'मंदिर ट्रस्ट की भूमिका धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों तक सीमित है।' हिमाचल हाईकोर्ट का ताजा फैसला इन्हीं सिद्धांतों की पुनः पुष्टि करता है और इसे अधिक ठोस एवं पारदर्शी रूप में सामने लाता है।

यह सवाल वर्षों से हिंदू समाज में गूंज रहा है; जब वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों और दान पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है, जब चर्च ट्रस्टों को सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता प्राप्त है, जब गुरुद्वारा प्रबंधक समितियाँ अपनी निधियों को अपने धार्मिक उद्देश्य से जोड़कर उपयोग करती हैं, जब इसी तरह बौद्ध, जैन या अन्य अपनी संपत्ति का उपयोग अपने पंथ के हित में करती हैं, तो हिंदू मंदिरों की निधियों पर सरकार का अधिकार क्यों?

यह वर्तमान की एक बड़ी सच्चायी है कि हिंदू मंदिरों से प्राप्त धनराशि सरकार के राजकोष में चली जाती है और कई बार उस धन से ऐसी योजनाएँ चलती हैं जिनका धर्म या मंदिर से कोई संबंध नहीं। दूसरी ओर, वही करदाता, जो मंदिर में दान देता है पहले से सरकार को कर भी दे चुका होता है। ऐसे में मंदिर में दान की गई राशि पर सरकार का दावा अनुचित और असमान है। हिमाचल हाईकोर्ट का यह निर्णय इसी असमानता को न्यायिक रूप से चुनौती देता है। अदालत ने कहा, 'जब सरकार मंदिर निधियों को अपने नियंत्रण में लेती है, तो वह श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ विश्वासघात करती है। मंदिर निधि कोई सार्वजनिक खजाना नहीं, यह धर्म और आस्था की निधि है।'

इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) पहले से लंबित है, जिसमें यह मांग की गई है कि हिंदू मंदिरों की आय का उपयोग धार्मिक, सांस्कृतिक और समाजसेवी कार्यों में हो। हिमाचल हाईकोर्ट का निर्णय इस याचिका को और प्रासंगिक बना देता है। अब आवश्यकता है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर शीघ्र सुनवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि भारत की धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू हो, किसी एक धर्म पर नियंत्रण और दूसरे को स्वतंत्रता देना धर्मनिरपेक्षता नहीं, असंतुलन है।

यह निर्णय धार्मिक संस्थानों की निधियों तक सीमित नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र में 'राज्य और आस्था के बीच की सीमाएँ' तय करने वाला फैसला है। अदालत ने यह सिद्ध किया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से दूरी नहीं, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और निष्पक्षता है। जब मस्जिद का धन वक्फ बोर्ड का, चर्च का धन चर्च ट्रस्ट का, और गुरुद्वारे का धन गुरु घर का है, तब मंदिर का धन भी देवता का होना चाहिए। भक्तों का अर्पण सरकार के राजकोष में नहीं, उनके ईश्वर की सेवा में लगना चाहिए।

इस आधार पर यहां निश्चित ही यही कहना होगा कि आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला कानून, धर्म और पारदर्शिता का संगम है। इसने स्थापित किया है कि मंदिर की निधि कोई 'सार्वजनिक फंड' नहीं, बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है। इस निर्णय ने एक नई बहस को भी जन्म दिया है, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के लिए समान स्वतंत्रता होगा या हिंदू संस्थानों के लिए नियंत्रण का पर्याय बनी रहेगी? अब यह जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय और नीति निमार्ताओं की है कि वे इस असमानता को समाप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि हर धार्मिक संस्था चाहे फिर वह मंदिर ही हो, अपने धर्म और विश्वास के अनुरूप स्वतंत्र रूप से संचालित होगी, उसमें किसी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वास्तव में हिमाचल हाईकोर्ट का यह निर्णय यही स्मरण कराता है कि दान भगवान का होता है, सरकार का नहीं।

आज का विचार
खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । शुक्रवार, 17 अक्तूबर, 2025 वर्ष 23, अंक 265, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत, सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ कानूनों की मजबूती सुनिश्चित कर रहा है: शाह

अमित शाह ने नई दिल्ली में सीबीआई द्वारा आयोजित भगोड़ों का प्रत्यर्पणः चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया

एजेंसी
नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को हर राज्य में भगोड़ों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक विशेष जेल बनाने का सुझाव दिया और कहा कि इंटरपोल के रेड नोटिस का सामना कर रहे भगोड़ों के पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाए ताकि प्रत्यर्पण के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार के दावों को कमजोर किया जा सके और सीमा पार उनकी बेरोकटोक आवाजाही को रोका जा सके।

विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी सहित कई भगोड़ों ने विदेशी अदालतों में अपने प्रत्यर्पण का विरोध करने के लिए भारतीय जेलों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया है। सीबीआई द्वारा आयोजित भगोड़ों का प्रत्यर्पण - चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा, जब तक हम विदेशों से भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारी संप्रभुता और हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले भगोड़ों के मन में भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रति भय पैदा नहीं करते, तब तक हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते।

वित्तीय अपराधों, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी सहित अन्य मामलों में वांछित भगोड़ों को वापस लाने के लिए विभिन्न देशों में भारत के 338 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित हैं।शाह ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी होने पर उनके पासपोर्ट को निगरानी सूची में शामिल किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, मौजूदा तकनीक के साथ ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब रेड नोटिस जारी होता है, तो भगोड़े की अंतरराष्ट्रीय

यात्रा को रोकने के लिए पासपोर्ट रद्द कर दिया जाना चाहिए। अगर हम इस प्रावधान को सिस्टम में शामिल कर सकें, तो इससे भगोड़ों को वापस लाने में मदद मिलेगी। सभी राज्य पुलिस प्रमुखों की भागीदारी वाले दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि भगोड़ों पर एक वैज्ञानिक डेटाबेस विकसित किया जाना चाहिए और इसे सभी राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए, जिसमें अपराधियों द्वारा किए गए अपराध का प्रकार, वर्तमान स्थान, देश में स्थित गिरोह और प्रत्यावर्तन प्रयासों की स्थिति शामिल होनी चाहिए।

उन्होंने प्रत्येक राज्य से भगोड़ों के लिए एक विशेष जेल बनाने का भी आग्रह किया, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य विदेशी अदालतों में भगोड़ों के इस तर्क को कमजोर करना है कि भारत में कैद की सजा होने पर उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, क्योंकि ये जेलें अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करती हैं। शाह ने कहा, यह जरूरी है क्योंकि भगोड़े विदेशी अदालतों में तर्क देते हैं कि भारत की जेलें मानकों के अनुरूप नहीं हैं, और यह भी कि उनके मानवाधिकारों की रक्षा नहीं की जाएगी। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर यह एक बहाना है, तो उन्हें यह मौका क्यों दिया जाए? हर राज्य की राजधानी में एक ऐसी जेल होनी चाहिए जो पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।

गृह मंत्री ने प्रत्येक राज्य के पुलिस विभाग में नार्को, आतंकवाद, वित्तीय और साइबर जगत से जुड़े अपराधियों के लिए एक समन्वय समूह बनाने का भी सुझाव दिया, जिसे खुफिया ब्यूरो और सीबीआई का सहयोग प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य पुलिस को प्रत्यर्पण मामलों के लिए एक विशेष विशेषज्ञ प्रकोष्ठ बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य पुलिस बल में ब्लू नोटिस को रेड नोटिस में बदलने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता है और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सीबीआई और आईबी को बहु-एजेंसी केंद्र के अंतर्गत विशेष इकाइयां बनानी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि इंटरपोल का ब्लू नोटिस किसी भगोड़े के ठिकाने की जानकारी हासिल करने के लिए जारी किया जाता है।रेड नोटिस का उद्देश्य उन्हें हिरासत में लेना होता है, जो आरोपपत्र दाखिल होने के बाद ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कई मामलों में राज्य पुलिस को ब्लू नोटिस मिलता है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी वह इसे रेड नोटिस के रूप में अद्यतन नहीं करती।

आंध्र प्रदेश बन रहा आत्मनिर्भर भारत की सफलता का प्रमुख केंद्र : मोदी

एजेंसी (हि.स.)
कुरनूल (आंध्र प्रदेश)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में आंध्र प्रदेश एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में राज्य नई औद्योगिक क्रांति, तकनीकी नवाचार और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में आज 13,430 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने आंध्र प्रदेश की क्षमताओं को नजरअंदाज कर न केवल राज्य का बल्कि पूरे देश का नुकसान किया। वह राज्य जो भारत के विकास को गति दे सकता था, उसे खुद अपने विकास के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अब एनडीए सरकार के तहत आंध्र प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। यह राज्य आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत बन रहा है।

उन्होंने कहा कि आज 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में आंध्र प्रदेश की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा, 2047 के विकसित भारत के संकल्प को ह्यस्वर्ण आंध्राह्ल

के लक्ष्य से नई ऊर्जा मिल रही है। तकनीक और नवाचार में आंध्र प्रदेश और उसके युवा हमेशा अग्रणी रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के तहत हम इस क्षमता को और सशक्त कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि गूगल आंध्र प्रदेश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हब स्थापित करने जा रहा है। यह निवेश न केवल राज्य बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है।मोदी ने बताया, गूगल का यह एआई हब विशाखापत्तनम को वैश्विक एआई और कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। इसमें शक्तिशाली एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, ऊर्जा स्रोत और अंतरराष्ट्रीय सबसी केबल नेटवर्क शामिल होंगे, जो भारत के पूर्वी तट से जुड़ेंगे। उन्होंने इसके लिए आंध्र प्रदेश के लोगों और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की दूरदर्शिता की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए आंध्र प्रदेश का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा, आंध्र के विकास के लिए रायलसीमा का विकास भी उतना ही जरूरी है। आज कुरनूल की भूमि पर शुरू हुए प्रोजेक्ट्स रायलसीमा के हर जिले में रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोलेंगे।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अर्वकल और कोप्पर्थी को आंध्र प्रदेश की नई औद्योगिक पहचान के रूप में विकसित कर रही है। इन औद्योगिक कॉरिडोरों से निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को 21वीं सदी के नए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही है। इस सफलता की नींव आत्मनिर्भर भारत का विजन है और आंध्र प्रदेश इस मिशन का प्रमुख केंद्र बन रहा है।

प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि निम्मलुरु में एडवांस्ड नाइट विजन प्रोडक्ट्स फैक्टरी का शुभारंभ भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यहां नाइट विजन उपकरण, मिसाइल सेंसर और ड्रोन गार्ड सिस्टम तैयार किए जाएंगे, जिससे भारत रक्षा उत्पादन और निर्यात दोनों में आत्मनिर्भर बनेगा।

आपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई

प्रधानमंत्री ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को भारत में बने आधुनिक उपकरणों की शक्ति दिखाई। मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे स्वदेशी ड्रोन, नाइट विजन और रक्षा तकनीक ने जो सफलता हासिल की, उस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। इससे साबित हुआ कि आत्मनिर्भर भारत की नीति केवल नारा नहीं, बल्कि भारत की वास्तविक ताकत बन चुकी है। उन्होंने आंध्र प्रदेश की सरकार के कुरनूल को भारत का ड्रोन हब बनाने के संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भविष्य की औद्योगिक क्रांति की रीढ़ बनने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय ड्रोन की भूमिका ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। आने वाले समय में कुरनूल ड्रोन सेक्टर में देश की ताकत बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का विजन नागरिक केंद्रित विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा, हम लगातार सुधारों के जरिए नागरिकों के जीवन को आसान बना रहे हैं। अब 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। सस्ती दवाइयां, सस्ता इलाज और आयुष्मान जैसी योजनाएं नागरिकों के जीवन में नई सहजता ला रही हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी में भारी कटौती की गई है और आंध्र प्रदेश में लोग जीएसटी बचत उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बिजली, सड़क, रेलवे और औद्योगिक विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि देश की ऊर्जा सुरक्षा में आंध्र प्रदेश की बड़ी भूमिका है। आज बिजली क्षेत्र में तीन हजार करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन परियोजना शुरू हुई है। इससे देश की ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस शासन के समय प्रति व्यक्ति बिजली खपत एक हजार यूनिट से भी कम थी और कई गांव अंधेरे में डूबे रहते थे।

'ऑपरेशन सिंदूर' भारत की बढ़ती स्वदेशी शक्ति का ज्वलंत प्रमाण है : राजनाथ सिंह

एजेंसी (हि.स.)
मुंबई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पुणे में कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' भारत की बढ़ती स्वदेशी शक्ति का एक ज्वलंत प्रमाण है, जो देश में आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के सरकार के अथक प्रयासों से प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पुणे में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को विश्वास और दृढ़ता जैसे गुणों के महत्व समझा रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि जब सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना शुरू किया, तो आरंभ में यह कठिन लग रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में घरेलू रक्षा विनिर्माण के विस्तार में कोई कसर न छोड़ते हुए पूरी कोशिश की गई। इसी संकल्प के कारण सकारात्मक परिणाम मिलने लगे।

उन्होंने कहा कि हमने रक्षा क्षेत्र में बदलाव का संकल्प लिया है क्योंकि देश की स्वतंत्रता के बाद से ही हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भर रहे हैं। हम हथियार खरीदने के आदी हो गए थे क्योंकि हमारे पास भारत में निर्माण करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी थी और हमारे पास रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने संबंधी कानून भी नहीं थे। इसमें बदलाव की आवश्यकता थी। अब हमारा संकल्प है कि भारत अपने सैनिकों के लिए स्वदेश में निर्मित हथियार बनाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने हमारे सैनिकों की वीरता देखी। उन्होंने कहा कि निर्धारित व्यापक लक्ष्य देश में निर्मित रक्षा उपकरणों के उपयोग से ही हासिल किया है। रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सालाना रक्षा उत्पादन 46 हजार करोड़ रुपये से बढकर रिकॉर्ड डेढ़ लाख करोड़ रुपये का हो गया है, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 33 हजार करोड़ रुपये का है। उन्होंने वर्ष 2029 तक तीन लाख करोड़ रुपये के रक्षा विनिर्माण लक्ष्य और 50 हजार करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य हासिल होने का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने विद्यार्थियों से शैक्षणिक उपलब्धियों से आगे बढकर सृजनकर्ता, नवोन्मेषक और राष्ट्रीय विकास में योगदानकर्ता बनने का आान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्ची सफलता केवल शैक्षणिक उपाधि हासिल करने में नहीं, बल्कि सामाजिक लाभ के लिए ज्ञान के सार्थक उपयोग में निहित है। रक्षा मंत्री ने प्रौद्योगिकी में विशेष रूप से एआई के प्रभाव का उल्लेख करते हुए इस आशंका को निर्मूल बताया कि इससे नौकरी जाने और मानव श्रम की आवश्यकता समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कभी मानव श्रम की जगह नहीं लेगा, बल्कि जो लोग एआई का उपयोग करते हैं, वे उन लोगों की जगह लेंगे जो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के सैन्य प्रमुखों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र के टूप कॉन्ट्रिब्यूटिंग कंट्रीज के आर्मी चीफ्सह्ल कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के सेना प्रमुख और उप-सेना प्रमुख अपने जीवनसाथियों सहित गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि सभी प्रतिभागी अपने-अपने देशों के श्रेष्ठ मूल्यों और आदर्शों के गौरवशाली प्रतिनिधि हैं। वे वैश्विक शांति और सतत समृद्धि के लिए अपने अनुभव, विशेषज्ञता और संकल्प का प्रतीक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक अब तक विश्वभर में 71 अलग-अलग मिशनों में

तैनात किए गए हैं। इन अभियानों का उद्देश्य निर्दोष लोगों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के दुखों को कम करना है। कठिन और दूरस्थ इलाकों में तैनात संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों ने अदम्य साहस और करुणा का परिचय दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में भारत बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन में दृढ़ विश्वास रखता है। हमारे शांति सैनिकों ने विश्व के सबसे चुनौतीपूर्ण अभियानों में उत्कृष्ट सेवा दी है। भारत ने शांति अभियानों में लैंगिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। महिला शांति सैनिकों ने स्थानीय समुदायों को सशक्त किया है और भरोसे का वातावरण बनाया है। जो राष्ट्र अपने वीर महिला और पुरुष सैनिकों को शांति स्थापना के इस पवित्र कार्य के लिए भेजते हैं, उन्हें ऐसे ढांचे विकसित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए, जिससे टूप कॉन्ट्रिब्यूटिंग कंट्रीज की आवाज अधिक सशक्त हो सके।

देशभर में कृषि विज्ञान केन्द्रों के नेटवर्क का विस्तार करना आवश्यकः शिवराज सिंह

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में वर्तमान में 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) हैं, जिनके नेटवर्क का विस्तार करने के साथ ही उन्हें छोटे किसानों के हित में मजबूती देना आवश्यक है। शिवराज सिंह गुरुवार को कृषि भवनमेंएक उच्चस्तरीय बैठक में देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्यों की समीक्षा के मौके पर अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों तक पहुंच के लिए देशभर में कार्यरत सबसे प्रमुख माध्यम हैं, इनकी भूमिका तकनीकी प्रसार, प्रशिक्षण एवं कृषि नवाचारों को किसानों तक पहुंचाने में है। शिवराज सिंह ने कहा कि केवीके को सरकार की किसान हितैषी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को किसानों की भलाई और उनकी जागरूकता के लिए उनके बीच पहुंचाना चाहिए।

बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने आईसीएआर के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि केवीके की कार्यप्रणाली को सुचारू करने

के साथ ही इनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इन्हें समुचित वित्तीय, मानव संसाधन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, शिवराज सिंह ने केवीकेके में कार्यरत वैज्ञानिकों व कर्मचारियों की योग्यता अनुरूप पदोन्नति और अकादमिक समता सुनिश्चित करने के लिए पहल करने पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रशिक्षण, अनुसंधान विस्तार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सभी केवीके में एकरूपता लाने के निर्देश दिए। साथ ही, शिवराज सिंह ने केवीकेके सभी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आयु तथा सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ के संबंध में अधिकारियों से समुचित समाधान करने के लिए चर्चा की। इस संबंध में राज्य सरकारों तथा नीति आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के स्तर पर भी समुचित हल के लिए पहल करने के निर्देश केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिए।

अब कोई भी बिहार को पुराने लालटेन युग में नहीं ले जा पाएगा : योगी आदित्यनाथ

एजेंसी (हि.स.)
पटना

भाजपा के नेता एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा के चुनावी रण में उतर चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को दूसरी जनसभा सहरसा में की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार को आज जब मेट्रो, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, वाटरवे के रूप में पहचान मिल रही है तो इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद)-कांग्रेस ने शिगूफा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। इससे यह लोग फर्जी मतदान कराकर गरीबों-दलितों के हकों पर डकैती डाल सकें। चुनाव में यह विकास की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि बिहार अब पुराने लालटेन युग में नहीं जाएगा, नीतीश जी (मुख्यमंत्री नीतीश कुमार) इसे एलईडी की दूधिया लाइट में

लेकर आगे बढ़ चुके हैं।

योगी आदित्यनाथ ने यहां नामांकन रैली में सहरसा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार आलोक रंजन झा, सोनबरसा से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार रत्नेश सादा, महिषी से गुंजेश्वर शाह व सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह (लोजपा) को जिताने की अपील की। योगी ने दोनों विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि फर्जी वोट डलवाएंगे, लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थयात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, पासपोर्ट पर फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग पर कहेंगे कि बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। कांग्रेस व राजद फिर से गरीबों के हकों पर डकैती डालने की साजिश कर रहे हैं। इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है, क्योंकि कांग्रेस व राजद ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था।

उप्र मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि यह अपने शासनकाल में भारत को अपमानित करते थे। घुसपैठ कराकर अराजकता फैलाते थे। राजद ने बिहार का नहीं, परिवार का विकास किया। राजग पूरे भारत के लिए सोचता है। 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बिहार में विकास नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। बाढ़ की समस्या का समाधान बढ़ रहा है। अब गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलता है। पहले यह कांग्रेस-राजद व उनके पार्टनर्स में बंट जाता था। योगी ने कहा कि जब भी अवसर मिला तो महापुरुषों की प्रेरणा से उप्र में हमने नया करने का कार्य किया है। जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि (सिताबदियारा) का जिक्र किया और कहा कि हमने उनका पावन स्मारक बनाया। 2017 में हमारी सरकार आई तो उनकी पत्नी के नाम पर चिकित्सालय का नामकरण किया। प्रयागराज में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अयोध्या से सीतामढ़ी तक रामजानकी मार्ग के माध्यम से अयोध्या की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का कार्य उप्र की डबल इंजन की भाजपा सरकार आपके साथ मिलकर रही है।

उन्होंने कहा कि बिहार के पास समृद्ध विरासत है। लोकतंत्र पर आंच आएगी तो बिहार से कोई जेपी इसे बचाने खड़ा हो जाएगा। बिहार ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को जन्म दिया, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। स्वतंत्र भारत में सोमनाथ मंदिर के पुनरोद्धार की बात हुई। पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि नहीं जाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक व नई आभा को वैश्विक जगत में प्रस्तुत करना है। कांग्रेस भले ही विरोध करेगी, लेकिन राष्ट्रपति के कारण भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व है। राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ की धरती पर गए। उन्होंने कहा कि भारत की आस्था का सम्मान और विरासत का संरक्षण होगा। विरासत ही विकास की नींव को पुख्ता करेगी।

केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में 1.41 लाख अतिरिक्त नए घरों को मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत 1,41,942 नए घरों को मंजूरी दी है। इसके बाद योजना के तहत कुल स्वीकृत घरों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में यह मंजूरी दी गई। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी भी शामिल हुए। यह आवास असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों लिए होंगे। बैठक में सचिव ने कहा कि घरों का निर्माण ऐसी जगहों पर होना चाहिए जहां सड़क, सार्वजनिक परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाएं हों।

अमेरिका जूझ रहा सरकारी शटडाउन से सीनेट की 15 दिन में नौ बार कोशिश

नहीं पारित हो सका वित्त पोषण विधेयक, डेमोक्रेट्स का नहीं मिला अतिरिक्त समर्थन

एजेंसी (हि.स.)

वाशिंगटन

संयुक्त राज्य अमेरिका इन दिनों सरकारी शटडाउन से जूझ रहा है। शटडाउन के 15 दिन गुजर गए। इस दौरान सीनेट ने नौ बार संकट से उबारने के लिए प्रयास किए। सीनेट ने बुधवार को भी सरकार को वित्त पोषण देने के लिए सदन से पारित रिपब्लिकन पार्टी के विधेयक को पारित कराने में विफल रही। सीनेट में वीरवार को फिर एक बार कोशिश होगी।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेट में बुधवार को मतदान में डेमोक्रेट्स का कोई अतिरिक्त समर्थन नहीं मिला। डेमोक्रेट्स स्वास्थ्य सेवा कर क्रेडिट के विस्तार की मांग कर रहे हैं। रिपब्लिकन को पांच और सीनेटरों को अपने पक्ष में करने के लिए राजी करना होगा। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने अप्रयुक्त अनुसंधान और विकास

डेमोक्रेट्स कर रहा स्वास्थ्य सेवा कर क्रेडिट के विस्तार की मांग

निधि से सैन्य कर्मियों को वेतन का भुगतान करने की तैयारी की है। वीरवार को दसवीं बार मतदान इस पर प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने चेतावनी दी कि यह अस्थायी समाधान है और अगर शटडाउन जारी रहा तो सैनिकों को महीने के अंत में अगला वेतन नहीं मिल पाएगा।

सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून ने कहा कि वह गुरुवार को पेंटागन को वित्तपोषित करने के लिए, साल भर के विनियोग विधेयक को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें अन्य वित्त पोषण विधेयक भी शामिल हो सकते हैं। इस विधेयक को पारित होने के लिए 60 मतों की आवश्यकता होगी। मतदान

फोटोः हि.स.

सुबह 10 बजे होगा। बताया गया है कि सीनेट रिपब्लिकन फंडिंग बिल पर 10वीं बार मतदान करेगी। काश पटेल ने ट्रंप का आभार जताया एफबीआई निदेशक काश पटेल ने बुधवार को घोषणा की कि ट्रंप प्रशासन ने सरकारी शटडाउन के बावजूद एफबीआई एजेंटों को भुगतान जारी रखने का फैसला किया है। यह फैसला इसलिए खास है कि लगभग सभी संघीय कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है।

काश पटेल ने ओवल ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति ट्रंप का इसके लिए आभार भी जताया। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा, एफबीआई की ओर से हम आपके बहुत बड़े ऋणी हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि शटडाउन के दौरान सेना को भुगतान करने के लिए अप्रयुक्त धन का उपयोग किया जाए।

सैनिकों को वेतन का भुगतान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सैन्य कर्मियों को वेतन न देना सैन्य तत्परता और सशस्त्र बलों की राष्ट्र की रक्षा और बचाव करने की क्षमता के लिए एक गंभीर और अस्वीकार्य खतरा प्रस्तुत करता है।

उन्होंने कहा कि इस स्थिति से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है। सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि पेंटागन वेतन भुगतान के लिए अप्रयुक्त अनुसंधान और विकास निधि का उपयोग कर रहा है। संघीय न्यायाधीश ने दिया दखल सरकारी शटडाउन पर सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी जिला न्यायाधीश सुसान इल्स्टन ने कहा कि नौकरी में कटौती राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती है और बिना सोचे-समझे की जा रही हैं। यह ऐसी मानवीय कीमत है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने नौकरियों में कटौती पर रोक लगाने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश भी जारी किया।

राजस्थान के बालोतरा में सड़क हादसा, चार दोस्तों की मौत

एक युवक की हालत गंभीर

एजेंसी (हि.स.)

बालोतरा (राजस्थान)

फोटोः हि.स.

बालोतरा जिले में सिणधरी थाना क्षेत्र के सड़ा गांव में मेगा हाइवे पर हुए सड़क हादसे में चार दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है। यह हादसा बुधवार आधीरात बाद करीब 1:30 बजे हुआ। यह हादसा ट्रेलर और स्कॉर्पियो में टक्कर से हुआ। दोनों वाहनों में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग की लपटों से घिरी स्कॉर्पियो में सवार युवकों को बाहर निकालने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हो पाए। हाइवे पर करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस और दमकल टीम के पहुंचने के बाद दोनों वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया गया।

पुलिस के अनुसार, गुड़ामालानी (बाड़मेर) के डाबड़ गांव निवासी पांच दोस्त काम से सिणधरी गए थे। वहां से लौटते समय यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान मोहनसिंह (35) पुत्र धूड़सिंह, शम्भूसिंह (20) पुत्र दीपसिंह, पांचाराम (22) पुत्र लुम्बाराम और प्रकाश (28) पुत्र सांपाराम के रूप में हुई है। वहीं स्कॉर्पियो चालक दिलीप सिंह गंभीर रूप से झुलस गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उनके घर से महज 30 किलोमीटर पहले हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर चालक ने जान जोखिम में डालते हुए स्कॉर्पियो के चालक को बाहर खींचने की कोशिश की और वह इसमें सफल रहा। झुलसे युवक को सिणधरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया।

जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक रमेश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान, डिप्टी नीरज शर्मा, उपखंड अधिकारी समंदर सिंह भाटी, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी वाकाराम चौधरी सहित परिवहन अधिकारी व प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। आरजीटी कंपनी और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

दुगार्पुर दुष्कर्म मामले पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी

एजेंसी (हि.स.)

कोलकाता

फोटोः हि.स.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने दुगार्पुर में दलित छात्रा के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी। राजभवन के एक अधिकारी ने गुरुवार सुबह इसकी पुष्टि की। राजभवन के इस अधिकारी के अनुसार, रिपोर्ट राज्यपाल के उस दौरे पर आधारित है जिसमें उन्होंने दुगार्पुर जाकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राज्यपाल बोस ने बुधवार को कोलकाता के एक वाणिज्यिक कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर गहरी चिंता जताई थी।

उन्होंने कहा था, हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जो घटनाएं सामने आई हैं, उनमें दुगार्पुर कांड भी शामिल है। अब यह कहना कठिन है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य है। यह घटना 10 अक्टूबर की रात की है। दुगार्पुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ने वाली ओडिशा की छात्रा के साथ उस समय सामूहिक दुष्कर्म हुआ जब वह अपने पुरुष साथी के साथ बाहर निकली थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी न्यायिक हिरासत में हैं। राज्यपाल ने इस घटनाक्रम पर शासन व्यवस्था की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, हम जो देख रहे हैं, वह केवल हिमशैल का ऊपरी हिस्सा है। इसके नीचे प्रशासन की अक्षमता छिपी हुई है, जो व्यवस्था चलाने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने राज्य के पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए। बोस ने कहा, राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारी है।

बांग्लादेश में जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह कराने के समय पर राजनीतिक दलों में गतिरोध

एजेंसी (हि.स.)

ढाका

बांग्लादेश में जुलाई चार्टर पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने के समय को लेकर राजनीतिक असहमति अंतरिम सरकार धर्मसंकट में है। संकेत हैं कि मुख्य सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनुस जल्द ही निर्णायक हस्तक्षेप कर सकते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने फरवरी में होने वाले आगामी राष्ट्रीय चुनाव के दिन ही जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखा है।

इसके उलट बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) जैसी पार्टियां जनमत संग्रह चुनाव से पहले कराने की मांग कर रही हैं। जमात और एनसीपी का तर्क है कि चार्टर पर जनता की राय मतदान से पहले जाननी चाहिए। ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिम सरकार कल

हमने जनमत संग्रह कब होगा, इस पर कोई निर्णय नहीं लियाः प्रो. डॉ. बदीउल

फोटोः हि.स.

(शुक्रवार) जुलाई के राष्ट्रीय (जुलाई) चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाली है इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इन मतभेदों को पाटने और हस्ताक्षर से पहले अनिश्चितता को दूर करने के प्रयास में सर्वसम्मति आयोग के अध्यक्ष डॉ. यूनुस ने बुधवार को प्रमुख राजनीतिक दलों और बंधनों के नेताओं से चर्चा की। चर्चा के बाद वामपंथी गठबंधन ने अनसुलझे मुद्दों का हवाला देते हुए घोषणा की कि वह चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। एनसीपी नेता अख्तर हुसैन ने कहा कि जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर करने के पार्टी के फैसले की समीक्षा की जा रही है। बताया गया है कि अंतरिम सरकार के विभाग भी जनमत संग्रह की समय-सीमा को लेकर विभाजित हैं। जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर समारोह कल राष्ट्रीय संसद के साउथ प्लाजा में निर्धारित है। इसमें कम से कम 30 राजनीतिक दलों के शामिल होने की उम्मीद है। जनमत संग्रह का मूल प्रस्ताव राष्ट्रीय सहमति आयोग का है। अब आयोग अंतरिम सरकार को संभावित तिथियों का सुझाव देते हुए एक औपचारिक पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है। आयोग के सदस्य प्रोफेसर डॉ. बदीउल आलम मजूमदार ने पुष्टि की है कि अभी तक समय सीमा तय नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा, हमने जनमत संग्रह कब होगा, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। चुनाव से पहले जनमत संग्रह कराने के समर्थकों का कहना है कि इससे राजनीतिक दलों को जनता की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। इस मसले पर बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की अध्यक्षता में स्थायी समिति ने सोमवार रात बैठक की। पार्टी ने अपने रुख की पुष्टि की कि जनमत संग्रह राष्ट्रीय चुनाव के साथ ही होना चाहिए।

संक्षिप्त-समाचार

खड़दह में तीन गिरफ्तार, अवैध असलहा बरामद

उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना जिले के खड़दह थाने की पुलिस ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक के बाद एक तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में एक 7 मिमी पिस्तौल, एक मैगजीन और 5 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, खड़दह थाने की टीम ने पहले छापा मारकर शमीम हुसैन उर्फ. गिल को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसके बयान के आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपित जीत सिकदर उर्फ. बबिन को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद, जीत सिकदर के बयान पर कार्रवाई करते हुए खड़दह थाने की टीम ने हालीशहर थाना इलाके में छापेमारी की और वहां से तीसरे आरोपित सुवेंदु मित्रा उर्फ. दीपु (31) को गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने 7 मिमी पिस्तौल, एक मैगजीन और पांच कारतूस बरामद किए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ जारी है और यह जांच की जा रही है कि हथियारों का इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया जाना था। मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अवैध पटाखों पर पुलिस की सख्ती, चार गिरफ्तार

टीटागढ़(उत्तर 24 परगना)। उत्तर 24 परगना जिले में पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान चलाते हुए घोला, मोहनपुर और टीटागढ़ में छापेमारी कर 82 किलो से अधिक पटाखे जब्त किए हैं। घोला थाने की पुलिस ने 22.5 किलो 'चॉकलेट बम' बरामद कर नारायण चंद्र मंडल (44) को गिरफ्तार किया। वहीं, मोहनपुर थाने ने राजा चौहान (33) को 16 किलो पटाखों के साथ पकड़ा। टीटागढ़ पुलिस ने दो अलग छापेमारियों में 28.64 किलो और 15.10 किलो पटाखे जब्त कर कनाई साव(45) और नंदू चौधरी (43) को गिरफ्तार किया है। सभी मामलों में धारा 223/288 बीएनएस और पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1950 की धारा 24/26 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि त्योहारों से पहले जिले में अवैध पटाखों की बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।

कांकेर में एक बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, 12 यात्री घायल

कांकेर/रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे-30 पर आज गुरुवार को सुबह लगभग चार बजे कांकेर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 30 पर जंगलवार कॉलेज के पास एक यात्री बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए। जिनमें सीआरपीएफ के दो जवान भी शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस तेज रफ्तार में थी और धुंध के कारण चालक को सामने खड़े ट्रक दिखाई नहीं दी, जिससे यह टक्कर हो गई। हाईवे पर ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। टक्कर इतनी दर्दनाक थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत कांकेर जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच पुलिस कर रही है।

सारंडा में नक्सलियों ने सड़क पर पेड़ गिराकर लगाया जाम

पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के घने सारंडा जंगल में नक्सली गतिविधियां एक बार फिर तेज होती दिख रही हैं। बुधवार की देर रात जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलबंगा गांव के पास भाकपा-माओवादी नक्सलियों ने दो बड़े पेड़ काटकर सड़क पर गिरा दिए और आवागमन ठप कर दिया। सड़क जाम करने के साथ ही नक्सलियों ने मौके पर बैनर टांग दिया, जिसमें अपनी मांगें और संदेश लिखे गए थे। यह घटना नक्सलियों की ओर से मनाए जा रहे प्रतिरोध सप्ताह के दौरान हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय नक्सली सड़क जाम करने के बाद बैनर लगाकर वहां से चले गए। पेड़ गिरने के कारण गांवों के बीच संपर्क मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस कार्रवाई के जरिए नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और पुलिस अभियानों के खिलाफ विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों नक्सलियों ने इसी इलाके में एयरटेल मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया था और आईईडी विस्फोट कर सुरक्षाबलों को निशाना बनाया था। उस हमले में एक जवान शहीद हो गया था जबकि दो जवान घायल हुए थे। पुलिस ने घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है और सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम जारी है।

मुठभेड़ में मैनपुरी के तीन लुटेरे गिरफ्तार, दो गोली लगने से घायल

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में थाना शिकोहाबाद व एसओजी पुलिस ने गुरुवार को मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरों सहित तीन को गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से घायल दो लुटेरों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि 11 अक्तूबर को थाना शिकोहाबाद क्षेत्रान्तर्गत नीमखेरिया की पुलिया पर एक व्यक्ति से लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही थी। थाना शिकोहाबाद प्रभारी अनुज कुमार व एसओजी प्रभारी प्रेम शंकर पांडेय पुलिस टीम के साथ गुरुवार को क्षेत्र में गश्त पर थे तभी सूचना मिली कि लूट के मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण मोटरसाइकिल से किसी घटना करने की फिराक में ड़ाहिनी बाम्बा की पटरी के पास शिकोहाबाद में घूम रहे है। पुलिस टीम ने चेकिंग करते हुए छीछामई नहर पटरी के पास घेराबंदी की तो पुलिस टीम पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी फायरिंग में 02 अभियुक्त नासिद उर्फ लंगडा पुत्र नकीम उर्फ हरजू व शाहरूख पुत्र यूनिस निवासी बडा हार थाना घिरोर मैनपुरी पैर में गोली लगने से घायल हो गये व एक अभियुक्त यूनिस उर्फ गुलफाम उर्फ अमीन निवासी बडा हार थाना घिरोर मैनपुरी को मोटरसाइकिल गिरने के कारण घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। घायल व्यक्तियों की पहचान लूट के मुकदमे में वांछित अभियुक्तों के रूप में हुई है। अभियुक्तगण के कब्जे से 03 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस ,05 जिंदा कारतूस, 01 लूट की मोटर साइकिल व 01 मोबाइल फोन, आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेन्स बरामद हुआ है।

हमास ने रेडक्रॉस को दो और बंधकों के शव सौंपे

समूह ने कहा-सभी मृत बंधक वापस, दावे पर ट्रंप भड़के

एजेंसी (हि.स.)

तेल अवीव

हमास ने रेडक्रॉस को दो और बंधकों के शव सौंप दिए। इसके बाद रेडक्रॉस के अधिकारियों ने दोनों शव इजराइली सेना को सौंप दिए। इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने इसकी पुष्टि की। हमास ने दावा किया है कि उसने अब सभी मृत बंधकों को वापस कर दिया है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, शवों को पहचान के लिए अबू कबीर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ले जाया गया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायल को रोके रखा है। अगर हमास समझौते को बरकरार नहीं रखता तो इजराइल की फिर गाजा पट्टी में वापसी होगी। अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार, इजराइली

फोटोः हि.स.

अधिकारियों ने कहा कि हमास की तरफ से सौंपे गए चौथे शव की पहचान फिलीस्तीनी नागरिक के तौर पर हुई है। वह बंधक नहीं था। आईडीएफ ने कहा कि युद्धविराम समझौते के तहत हमास को सभी जीवित और मृत बंधकों को सोमवार तक सौंपना था। इससे पहले हमास ने मंगलवार रात गाजा सिटी में रेडक्रॉस को चार शव सौंपे थे। इन्हें बाद में इजरायली सेना को सौंपा गया। सोमवार को हमास ने अंतिम 20 जीवित बंधकों को रिहा किया था। युद्धविराम समझौते की शर्तों के अनुसार सभी 28 मृत बंधकों के शव सोमवार दोपहर तक लौटाए जाने थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि अगर हमास ने निशस्त्रीकरण से इनकार किया तो तबाही मच जाएगी। नेतन्याहू ने सीबीएस न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा है कि अगर हमास निशस्त्रीकरण के लिए सहमत नहीं होता है, तो तबाही मचनी तय है।

यह पूछने पर कि जब इजराइली सेना अभी भी गाजा के कुछ हिस्सों में तैनात है और हमास पट्टी पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर रहा है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि युद्ध समाप्त हो गया है? नेतन्याहू ने कहा, हम शांति को एक मौका देने के लिए सहमत हुए हैं। इजराइल ने हमास के दावों को टालमटोल की रणनीति बताकर खारिज कर दिया है और धमकी दी है कि अगर आतंकवादी समूह शेष शवों को तुरंत वापस नहीं करता है तो वह सहायता सीमित कर देगा। मिस्र के साथ राफाह सीमा बंद कर दी जाएगी। और लड़ाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मंगलवार को कहा कि हमास ने मध्यस्थों को मृत बंधकों के बारे में धोखे में रखा।

भारी मात्रा में संदिग्ध ब्राउन शुगर जब्त, 3 गिरफ्तार

इंफाल। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने कांगपोकपी के पुलिस अधीक्षक अभिनव की देखरेख में संयुक्त अभियान के दौरान संदिग्ध ब्राउन शुगर से भरे 225 साबुनदानी जब्त किए, जिनका वजन साबुनदानी समेत 9.844 किलोग्राम था। मणिपुर पुलिस ने गुरुवार को आधिकारिक रूप से बताया गया कि यह अभियान खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने एसपी (एल एंड ओ) कांगपोकपी, एसडीपीओ कांगपोकपी, एसडीपीओ सपरमेना और ओसी कांगपोकपी पुलिस स्टेशन ने 16वीं असम राइफल्स और 112वीं बटालियन सीआरपीएफ के कर्मियों के साथ मिलकर बीते मंगलवार को लक्षित अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिनकी पहचान एक दंपति, वेनेइचोंग लहुंगडिम और थोंगखोपाओ लहुंगडिम तथा थांगमिनलुन हाओकिप के रूप में की गयी है। अधिकारियों ने तस्करी में इस्तेमाल की गई एक ऑल्टो कार, एक डीजल ऑटो और चार मोबाइल फोन भी बरामद किए। आरोपित फिलहाल हिरासत में हैं और अवैध खेप के स्रोत और नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

अलग-अलग अभियानों में 5 उग्रवादी गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)

इंफाल

फोटोः हि.स.

हिंसाग्रस्त मणिपुर में पुलिस एवं सुरक्षा बलों का धर-पकड़ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में अलग-अलग संगठनों के पांच कैडरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपितों से सघन पूछताछ जारी रखे हुए है। मणिपुर पुलिस ने गुरुवार को आधिकारिक बयान में बताया है कि बीते बुधवार को सुरक्षा बलों ने इंफाल पूर्व जिले के एंड्रो थानांतर्गत नगारियान पहाड़ी की तलहटी से इंफाल पूर्व जिले के हुइकाप गांव के पीआरईपीएके के 02 (दो) सक्रिय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। जिनकी पहचान लैटोनजम लकी सिंह (32) और सोरैशाम अथोई सिंह (42) के रूप में की गयी है। उनके पास से दो मोबाइल फोन जब्त किए गए। उसी दिन सुरक्षा बलों ने केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के एक सक्रिय कार्यकर्ता, मोहम्मद इमरान खान उर्फ लींगकपा (20) निवासी कैरांग चिंग्या अवांग लेइकाई, इंफाल पूर्व जिले को उसके निवास से गिरफ्तार किया। जबकि, बीते मंगलवार को पुलिस ने इंफाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई थानांतर्गत हाओबाम मारक लौरेम्बम लेइकाई क्षेत्र से यूएनएलएफ (पी) के 02 (दो) सक्रिय कार्यकताओं को गिरफ्तार किया। जिनकी पहचान बिष्णुपुर जिले के नारानसेना ममांग लेइकाई निवासी लेइशांगथेम शिंघाजीत मैतेई (22) और बिष्णुपुर जिले के थिनुंगेई मयाई लेइकाई निवासी सोरोखाइबाम दयानंद सिंह उर्फ नगनबा (28) के रूप में की गयी है। वे इंफाल पश्चिम जिले के हाओबाम मारक लौरेम्बम लेइकाई क्षेत्र के निवासियों को धमकाने में शामिल थे। उनके कब्जे से मैगजीन सहित एक 9 मिमी पिस्तौल, दो मोबाइल फोन बरामद किया गया। दूसरी ओर सुरक्षा बल विभिन्न जिलों के सीमांत और संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी अभियान और क्षेत्र नियंत्रण जारी रखे हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर आवश्यक वस्तुओं से लदे 130 वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई है।

कोलकाता समेत कई जिलों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी

बालू तस्करी मामले की जांच तेज

एजेंसी (हि.स.)

कोलकाता

पश्चिम बंगाल में बालू तस्करी के मामलों की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार सुबह एक बार फिर बड़ा अभियान चलाया। ईडी अधिकारियों ने तड़के कोलकाता, झाड़ग्राम, आसनसोल समेत राज्य के कुल 7 स्थानों पर एकसाथ छापेमारी की। बताया गया है कि कोलकाता के बेंटिंग स्ट्रीट, झाड़ग्राम के लालगढ़ और गोपीवल्लभपुर तथा आसनसोल के मुरगाशोल क्षेत्र में ईडी की टीमें पहुंची हैं। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई बालू तस्करी से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के तहत की जा रही है। पिछले महीने भी ईडी ने झाड़ग्राम के गोपीवल्लभपुर इलाके में शेख जहिरुल शेख नामक व्यक्ति के घर छापा मारा था। स्थानीय लोगों ने बताया था कि वह पहले ग्राम पुलिस में कार्यरत था लेकिन बाद में नौकरी छोड़ कर बालू के कारोबार में उतर गया और देखते ही देखते उसकी संपत्ति में

तेजी से वृद्धि हुई। उस छापेमारी के करीब एक महीने बाद ईडी का यह नया अभियान शुरू हुआ है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई राज्य में जारी अवैध बालू कारोबार की गहराई तक जांच से जुड़ी है। गौरतलब है कि हाल ही में ईडी ने नगर निकायों में भर्ती घोटाले की जांच में भी सक्रियता दिखाई थी। उस समय एजेंसी ने राज्य के मंत्री सुजीत बसु के सॉल्टलेक स्थित कार्यालय सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। राज्य में ईडी की लगातार होती कार्रवाइयों से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। एजेंसी का कहना है कि यह छापेमारी केवल अवैध लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की जा रही है, जिसमें कई कारोबारी और प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

प्राकृतिक

धरती की गोद से फूटता उबलता रहस्य

तातापानी जहां आस्था और विज्ञान दोनों करते हैं प्रणाम

साल भर बहता रहता है गर्म पानी

एजेंसी (हि.स.)

बलरामपुर

छत्तीसगढ़ के उत्तर में बसे बलरामपुर जिले का तातापानी एक ऐसा नाम जो सुनते ही रहस्य और रोमांच से भर देता है। यह वह जगह है जहाँ धरती खुद सांस लेती है, और उसकी गर्म सांसें जल बनकर कुंडों से फूटती हैं। यहां साल भर बहने वाला गर्म पानी न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से यह भू-ऊष्मीय अद्भुत घटना का परिणाम है। तातापानी अब प्रदेश के प्रमुख पर्यटन और शोध केंद्रों में अपनी पहचान बना चुका है।

तातापानी का प्राकृतिक रहस्य

बलरामपुर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित तातापानी में धरती की गहराइयों से कई स्थानों पर 90 से 98 डिग्री सेल्सियस तापमान का पानी निकलता है। यह पानी सल्फर और खनिज लवणों से युक्त है, जिसके कारण इसे स्नान और औषधीय दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है। स्थनीय लोगों का मानना है कि इस जल से त्वचा रोग, गठिया और जोड़ों का दर्द जैसे कई रोगों में आराम मिलता है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण रायपुर के वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक डॉ. अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि, तातापानी क्षेत्र में भू-ऊष्मीय ऊर्जा का स्त्रोत धरती के भीतर मौजूद मैग्मा और गैसों से उत्पन्न ताप है। यहां की भूमि की दरारों से गर्म जल सतह पर आता है, जो प्राकृतिक रूप से सल्फरयुक्त है। यह क्षेत्र भू-ऊष्मीय मानचित्र में 'हाई टेम्परेचर जोन' के रूप में दर्ज है, और भविष्य में जियोथर्मल एनर्जी उत्पादन की भी बड़ी संभावना रखता है। उन्होंने आगे कहा कि, तातापानी छत्तीसगढ़ का वह दुर्लभ स्थान है, जहां धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक अध्ययन दोनों साथ-साथ चलते हैं। यहां शोध के लिए देश के कई संस्थान रुचि दिखा रहे हैं।

पर्यटन और धार्मिक महत्त्व

यह स्थल केवल वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आस्था और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर वर्ष मकर संक्रांति पर यहां तातापानी महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु और पर्यटक स्नान करने, पूजा-अर्चना करने और मेले का आनंद लेने पहुंचते हैं। पास ही बनी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और आस-पास के पहाड़ी झरनों से यह स्थान और भी मनोहारी लगता है। स्थानीय निवासी रामप्रसाद गुप्ता बताते हैं कि, यहां का जल सर्दियों में भी इतना गर्म रहता है कि लोग सीधे कुंड से सब्जी और अंडे तक उबाल लेते हैं। पहले लोग इसे चमत्कार मानते थे, अब वैज्ञानिक भी इसकी ताकत को स्वीकार कर रहे हैं। तातापानी वह जगह है जहां धरती की धड़कन सुनाई देती है। यह सिर्फ आस्था का स्थल नहीं, बल्कि विज्ञान का जीवंत उदाहरण भी है। यहां की उष्मा हमें याद दिलाती है कि हमारी पृथ्वी सिर्फ मिट्टी नहीं एक जीवंत शक्ति है, जो हर पल उफनती और फूटती रहती है। बलरामपुर का तातापानी आज भी कहता है जो धरती को समझना चाहता है, उसे पहले उसकी गर्मी को महसूस करना होगा।

राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए अहमदाबाद की सिफारिश

खेल मंत्री बोले, भारतीय खेलों के लिए ऐतिहासिक पल

❍ कहा, यह फैसला खेल इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अहमदाबाद को 2030 शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में अनुशंसा किए जाने को 'भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक पल' बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला भारत के खेल इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

डॉ. मांडविया ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, 2030 के शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद को प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित करने के लिए मैं कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की कार्यकारी बोर्ड का आभारी हूं। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की वैश्विक खेल शक्ति के रूप में बढ़ती प्रतिष्ठा को दशार्ता है। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत के 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के सपने को भी मजबूती देगा।

उन्होंने कहा, 'यह केंद्र सरकार की दृष्टि के अनुरूप एक बड़ा कदम है। हाल ही में नई दिल्ली में सफलतापूर्वक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन कर भारत ने अपनी संगठन क्षमता साबित की है। बीते एक दशक में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना, नीतिगत सुधारों, खेल विज्ञान और वित्तीय सहयोग के जरिए हम 'चैंपियनों का देश' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मांडविया ने कहा कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में हमेशा शानदार प्रदर्शन किया है और यह सिफारिश भारत के बढ़ते खेल प्रभाव का प्रमाण है। गौरतलब है कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की कार्यकारी बोर्ड ने अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में अनुशंसित किया है। यह अनुशंसा अब 26 नवंबर 2025 को होने वाली जनरल असेंबली में अनुमोदन के लिए रखी जाएगी। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल शताब्दी वर्ष में आयोजित होंगे और 74 सदस्य देशों के बीच सहयोग, समावेशिता और खेल उत्कृष्टता का प्रतीक बनेंगे। यह आयोजन भारत के वैश्विक खेल केंद्र बनने के विजन को भी और मजबूती देगा।

ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक चैंपियन एरियर्न टिटमस ने तैराकी से लिया संन्यास

❍ ओलंपिक में चार बार स्वर्ण पदक विजेता रही

एजेंसी (हि.स.)
मेलबर्न

फोटोः हि.स.

ऑस्ट्रेलिया की चार बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैराक एरियर्न टिटमस ने 25 वर्ष की उम्र में प्रतिस्पर्धी तैराकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। टिटमस ने बुधवार को अपना निर्णय सार्वजनिक किया, जिससे उनका शानदार करियर समाप्त हो गया—एक ऐसा करियर जिसमें उन्होंने अमेरिकी स्टार कैटी लेडेकी के साथ खेल इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विताओं में से एक को जन्म दिया।

टिटमस ने आठ ओलंपिक पदक और चार विश्व खिताब अपने नाम किए हैं। उनका यह फैसला ऑस्ट्रेलिया के लिए चौंकाने वाला है क्योंकि वे लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक में वापसी की योजना बना रही थीं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में टिटमस ने कहा, यह बहुत कठिन फैसला था, लेकिन मैं इससे खुश हूं। मुझे तैराकी से हमेशा प्यार रहा है। यह मेरा बचपन का सपना था। लेकिन कुछ समय पूल से दूर रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जीवन में कुछ चीजें मेरे लिए तैराकी से भी ज्यादा अहम हैं।

टिटमस ने पेरिस ओलंपिक में 400 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल में एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतकर सुर्खियां बटोरी थीं। इसे रेस ऑफ द सेंचुरी कहा गया था, जब उन्होंने लेडेकी और कनाडा की समर मैकिन्टॉश को पछाड़कर अपना खिताब बरकरार रखा। पेरिस ओलंपिक से आठ महीने पहले टिटमस ने अंडाशय से सौम्य ट्यूमर हटवाने के लिए सर्जरी करवाई थी। उन्होंने बताया कि इस स्वास्थ्य चुनौती ने उन्हें तैराकी के बाहर के जीवन के महत्व को समझने में मदद की। उन्होंने कहा, इन स्वास्थ्य चुनौतियों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि मेरे लिए वास्तव में क्या सबसे अहम है।

एरियर्न टिटमस 200 मीटर फ्रीस्टाइल में विश्व रिकॉर्ड अपने नाम के साथ संन्यास ले रही हैं। उन्होंने कहा, स्विमिंग के अलावा भी मेरे कई निजी लक्ष्य हैं। अब मैं जीवन के नए अध्याय के लिए बहुत उत्साहित हूं।

बॉक्सिंगबे और एपीएफसी इंडिया यूएफसी ऐप पर लाइव स्ट्रीम करेंगे

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

बॉक्सिंगबे मुक्केबाजी प्रतियोगिता का दिसंबर में अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप (यूएफसी) ऐप पर वैश्विक स्तर पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

यह भारत में होने वाली पहली मुक्केबाजी प्रतियोगिता होगी जिसकी लाइव स्ट्रीम की जाएगी। भारतीय मुक्केबाजी परिषद (आईबीसी) ने गुरुवार को यह घोषणा की। मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार यूएफसी ऐप पर लाइव स्ट्रीम होने वाली पहली श्रृंखला की प्रतियोगिताओं में पांच दिसंबर को एंथनी पेटिस फाइटिंग चैम्पियनशिप (एपीएफसी) इंडिया वन और 21 दिसंबर को होने वाली बॉक्सिंगबे4 शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन हैदराबाद, बेंगलुरु और विशाखापत्तनम में किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम पर्थ पहुंची

एजेंसी (हि.स.)
पर्थ

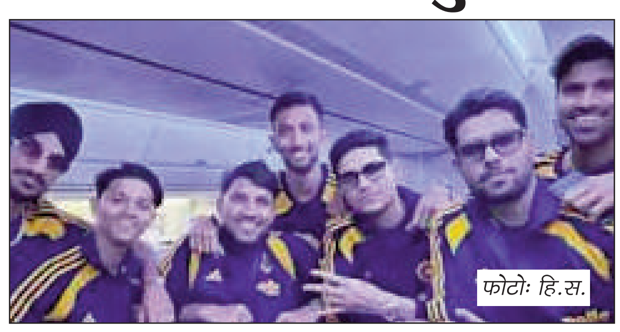
फोटोः हि.स.

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा तथा नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल सहित भारतीय एकदिवसीय टीम के प्रमुख सदस्य 19 अक्तूबरसे आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की श्रृंखला के लिए गुरुवार को यहां पहुंच गये।

कोहली, रोहित और गिल के अलावा पहले बैच के साथ यहां पहुंचने वाले अन्य खिलाड़ियों में केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी तथा सहयोगी स्टाफ के कुछ सदस्य शामिल थे।मुख्य कोच गौतम गंभीर तथा टीम और कोचिंग स्टाफ के अन्य सदस्य आज दिन में टीम से जुड़ेंगे क्योंकि वे बुधवार को दिल्ली से शाम की उड़ान से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए थे। वनडे श्रृंखला का पहला मैच यहां रविवार को खेला जाएगा। उसके बाद अगले दो मैच एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में खेले जाएंगे। इसके बाद 29 अक्तूबरसे पांच मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला शुरू होगी। इस साल मार्च में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद रोहित और कोहली का यह पहला अंतरराष्ट्रीय मैच होने के कारण इस श्रृंखला को लेकर काफी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि यह श्रृंखला इन दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। यह दोनों पहले ही टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वे कम से कम 2027 वनडे विश्व कप तक खेलना जारी रखना चाहते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को नए कप्तान गिल का समर्थन हासिल है जिनका मानना है कि उनका अनुभव वनडे टीम के लिए काफी मायने रखता है।

अंडर-20 विश्व कपः अर्जेंटीना और मोरक्को में होगा खिताबी मुकाबला

सैंटियागो (चिली)। अर्जेंटीना ने कुछ विषम पलों से गुजरने के बाद आठवीं बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई जहां उसका सामना मोरक्को से होगा। अर्जेंटीना को सेमीफाइनल में कोलंबिया की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा लेकिन आखिर में वह 1-0 से जीत हासिल करने में सफल रहा। माटेओ सिल्वेट्टी ने 72वें मिनट में अर्जेंटीना के लिए गोल किया जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। मोरक्को ने एक अन्य सेमीफाइनल में पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 5-4 से हराकर पहली बार अंडर-20 विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया। निर्धारित समय में स्कोर 1-1 से बराबर था।

फॉस्टिनो ओरो, जोस मार्टिनेज, माई नारवा बने जीसीएल कंटेंडर्स चैंपियन

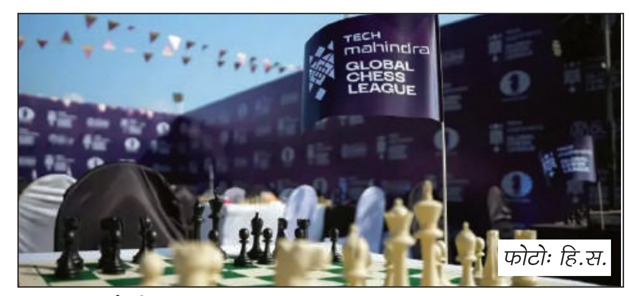

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
मुंबई

अर्जेंटीना के 12 वर्षीय खिलाड़ी फॉस्टिनो ओरो ने यहां जीसीएल कंटेंडर्स नॉकआउट चैलेंजर्स राउंड में प्रोडिजी अंडर 21 श्रेणी का खिताब जीता जबकि ग्रैंडमास्टर जोस मार्टिनेज और महिला ग्रैंडमास्टर माई नारवा क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग के चैंपियन बने।

यह तीनों खिलाड़ी अब ग्लोबल शतरंज लीग (जीसीएल) के तीसरे सत्र के दौरान आधिकारिक दूत के रूप में काम करेंगे जिसे टेक महिंद्रा और विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था फिडे के संयुक्त प्रयास से 13 से 24 दिसंबर, 2025 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा।

शतरंज के मेसी के नाम से मशहूर ओरो ने एक रोमांचक फाइनल में भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रणव आनंद को हराया, जबकि ग्रैंडमास्टर जोस मार्टिनेज ने अमेरिका के ब्लिट्ज विशेषज्ञ एंड्रयू टैंग को पराजित किया। एस्टोनिया की नारवा ने यूक्रेन की महिला ग्रैंडमास्टर यूलिया ओसमक को हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता।

हम सभी को जिंदगी की अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना चाहिए

हर साल 17 अक्तूबर को विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को यह समझाना है कि जिंदगी में होने वाले अचानक हादसे सिर्फ पलभर में सब कुछ बदल सकते हैं। चाहे वह सड़क पर हुआ एक्सीडेंट हो, घरेलू हिंसा हो या कोई प्राकृतिक विपदा-ऐसी घटनाएं न सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि मन पर भी गहरा असर छोड़ती हैं। आज के समय में, जब जीवन बहुत तेजी से बदल रहा है और जोखिम हर जगह मौजूद हैं।

वर्ल्ड ट्रॉमा डे का महत्व

ट्रॉमा के कारणों, लक्षणों और रोकथाम के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना। ज्यादातर सड़क दुर्घटना के कारण ही ट्रॉमा के मामले सामने आते हैं, इसलिए वर्ल्ड ट्रॉमा डे मनाने का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना है। जैसे- नशे में गाड़ी चलाने से बचना, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहनना, ड्राइविंग के नियमों को फॉलो करना। ट्रॉमा से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभावित होता है। इसलिए, इस समस्या से पीड़ित लोगों को समर्थन देने और संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है।

इतिहास

इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2011 में हुई, तभी से 17 अक्तूबरका दिन हर साल वर्ल्ड ट्रॉमा डे के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ट्रॉमा से शिकार व्यक्ति की उचित देखभाल के लिए लोगों को जागरूक करना है। किसी भी हादसे के दौरान व्यक्ति को समय पर ट्रॉमा से निकालने के महत्व को बढ़ावा देना है।.

क्यों मनाते हैं ये दिन ?

विश्व आघात दिवस का मकसद केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि समाज को यह भी समझाना है कि समय रहते अगर सावधानी बरती जाए, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दिन खासतौर पर कुछ बातों पर जोर दिया जाता हैः

- ❑ लोगों को समझाना कि आघात क्या होता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है।
- ❑ हर इंसान तक सही इलाज पहुंचाना, ताकि अगर किसी को आघात हो जाए, तो वह समय पर इलाज पा सके।
- ❑ पीड़ितों की मदद करना, उन्हें मानसिक और भावनात्मक सहारा देना।
- ❑ ऐसे कदम उठाना, जिससे भविष्य में हादसों की संख्या कम हो और ज़िंदगियां बचाई जा सकें।
- ❑ समुदाय में सहयोग बढ़ाना, ताकि सभी मिलकर एक सुरक्षित माहौल बना सकें।

ट्रॉमा के मुख्य कारण

- ♦ दुर्घटनाएं - सड़क पर हुए एक्सीडेंट, कहीं से गिरना या काम करते हुए चोट लगना।
- ♦ हिंसा - किसी का शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक तौर पर शोषण होना।
- ♦ प्राकृतिक आपदाएं - जैसे भूकंप, बाढ़ या तूफान जो अचानक जान-माल का नुकसान कर देते हैं।
- ♦ निजी हानि - किसी अपने की मौत या जीवन में आया बड़ा बदलाव भी मन को झकझोर सकता है।

लक्षण

आघात का असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग तरह से होता है। कुछ लोगों में इसके शारीरिक संकेत होते हैं, जैसे शरीर में लगातार दर्द, थकान या घाव। वहीं कुछ लोगों में मानसिक और भावनात्मक लक्षण दिखाई देते हैं-जैसे डर, चिंता, गुस्सा, नींद न आना, या समाज से दूरी बना लेना। अगर किसी में ये बदलाव नजर आएं, तो उसे अकेला न छोड़ें। उसकी मदद करें या किसी विशेषज्ञ से मिलने की सलाह दें। आघात से जुड़े मामलों में सबसे अहम होता है समय पर मदद मिलना। कई बार लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उन्हें आघात हुआ है या उन्हें मदद की जरूरत है। अगर समाज में जागरूकता होगी, तो हादसों के बाद लोग शर्म या डर के बजाय इलाज की तरफ बढ़ेंगे।

आघात का वैश्विक बोझ

आघात दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, जो हर साल लाखों लोगों की जान लेती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के अनुसार, हर साल लगभग 5.8 मिलियन लोग चोटों से मरते हैं, जो दुनिया भर में होने वाली मौतों का लगभग 10% है। यह आघात को दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक बनाता है, जो कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों के बराबर है।

आघात पर प्रमुख वैश्विक आंकड़े

सड़क यातायात दुर्घटनाएँः हर साल लगभग 1.3 मिलियन लोग सड़क यातायात दुर्घटनाओं के कारण मरते हैं, और 20 से 50 मिलियन लोग गैर-घातक चोटों से पीड़ित होते हैं। यह 5-29 वर्ष की आयु के बच्चों और युवा वयस्कों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। **कार्यस्थल पर चोटेंः** वैश्विक स्तर पर, यह अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 374 मिलियन गैर-घातक कार्य-संबंधी चोटें होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक दुर्घटनाओं या कार्य-संबंधी बीमारियों से 2.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। **गिरना और घरेलू दुर्घटनाएँः** प्रत्येक वर्ष गिरने से लगभग 684,000 लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें वृद्ध लोग सबसे अधिक असुरक्षित समूह होते हैं। **हिंसा और हमलेः** हिंसा के कृत्यों के परिणामस्वरूप विश्व भर में लगभग 1.6 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है, तथा बड़ी संख्या में गैर-घातक चोटें भी आती हैं, जिनमें चिकित्सा की आवश्यकता होती है।

भारत में आघात का प्रभाव

भारत, अपनी विशाल आबादी और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण, सड़क दुर्घटनाओं और कार्यस्थल पर चोटों के कारण होने वाली चोटों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि का अनुभव करता है। आघात भारत में अस्पताल में भर्ती होने के शीर्ष कारणों में से एक है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भारी बोझ डालता है।

सड़क यातायात दुर्घटनाएंः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 450,000 सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 150,000 से अधिक मौतें होती हैं और 300,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। कार्यस्थल पर चोटेंः भारत में हर साल व्यावसायिक दुर्घटनाओं के कारण लगभग 48,000 मौतें होती हैं, और इससे भी ज्यादा लोग गैर-घातक चोटों से पीड़ित होते हैं। निर्माण, खनन और विनिर्माण जैसे उद्योग विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले हैं। गिरना और घरेलू दुर्घटनाएंः भारत में गिरना चोट लगने का एक प्रमुख कारण है, खासकर बुजुर्गों के बीच। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के एक अध्ययन से पता चला है कि 25,000 में भारत में 2021 से ज्यादा मौतें दुर्घटनावश गिरने के कारण हुईं। हिंसा और हमलेः घरेलू हिंसा और हमलों सहित हिंसा भी भारत में आघात के मामलों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 30% महिलाओं ने किसी न किसी समय शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है।

रोकथाम

आघात की घटनाओं को कम करने के लिए रोकथाम बहुत जरूरी है। दुर्घटनाओं और चोटों को रोकने में सरल उपाय काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

सड़क सुरक्षा उपायः सीटबेल्ट और हेलमेट का उपयोगः सीटबेल्ट और हेलमेट पहनने से सड़क यातायात दुर्घटनाओं में गंभीर चोटों का खतरा काफी कम हो सकता है। गति सीमा और यातायात नियमः यातायात नियमों का सख्ती से पालन, साथ ही स्पीड कैमरे और जुमार्ने का प्रयोग दुर्घटनाओं को रोकने में मदद कर सकता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चरः सुरक्षित सड़कें बनाना, पैदल यात्री क्रॉसिंग स्थापित करना, तथा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था में सुधार करना दुर्घटनाओं को कम कर सकता है।

कार्यस्थल सुरक्षाः प्रशिक्षण और शिक्षाः कार्यस्थल पर सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग पर कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देने से दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। सुरक्षा उपकरणः उच्च जोखिम वाली नौकरियों में काम करने वाले श्रमिकों को हेलमेट, दस्ताने, हार्नेस और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। श्रमदक्षता शास्त्रः कार्यालयों में उचित एर्गोनॉमिक प्रथाओं से पीठ दर्द और कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी मस्कुलोस्केलेटल चोटों को रोका जा सकता है।

गृह सुरक्षाः बाल सुरक्षा गृहः सुरक्षा द्वारों का उपयोग, फर्नीचर को सुरक्षित रखना, तथा धूम्रपान डिटेक्टर लगाना बच्चों को चोट लगने से बचा सकता है। बुजुर्गों के लिए गिरने से बचावः हैंडरेल लगाना, ढीले कालीन हटाना, तथा अच्छी रोशनी सुनिश्चित करना, वृद्धों को गिरने से बचाने में मदद कर सकता है।

हरियाणा सरकार की ओर से पूरे किए गए संकल्प

हमने पिछले विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प-पत्र के 217 में से 46 वादों को एक साल में ही पूरा कर दिखाया है।यही नहीं, 158 वादों पर काम प्रगति पर है।यह एक वर्ष का समय भले ही कम है, लेकिन हमने जिस नॉन-स्टाप विकास का संकल्प लिया था।उसकी सिद्धि में यह एक वर्ष विकास की तिगुणी गति का साक्षी है।हम इसी वित्त वर्ष में कुल 90 संकल्प पूरे कर लेंगे।

1. नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 17 अक्तूबर, 2024 को 24,000 युवाओं को ग्रुप-सी की सरकारी नौकरियां दी गई।

2. इसके अलावा ग्रुप ए व बी के हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 01 अप्रैल 2024 से 13 नवंबर 2024 तक कुल 1311 उम्मीदवारों का चयन किया है।

3. सभी नागरिक जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में 18 अक्तूबर, 2024 से किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू की गईं।

4. नवम्बर, 2024 में आयोजित पहले विधानसभा सत्र में ही अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा, अतिथि संकाय और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की।

5. सभी 24 फसलों के दाने-दाने की खरीद एम.एस.पी. पर करने की अधिसूचना 19 दिसम्बर, 2024 को जारी की गई।

6. किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए ई-खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ई-गेट पास बनाने की सुविधा दी। अब किसान अपनी सुविधा अनुसार अपनी सारी फसल का एक गेट पास बनाकर मंडी में बेच सकता है।

7. खरीफ सीजन-2024 से किसानों की फसल खरीद का पैसा फसल का खरीद के रसीद कटने के 48 घंटे के अन्दर डी.बी.टी. के माध्यम से कर दिया जाता है।

8. विधानसभा में 18 नवम्बर, 2024 को बिल पास करके हरियाणा के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया।

9. 'हर घर-हर गृहणी' योजना के तहत प्रदेश के 15 लाख से अधिक अंत्योदय तथा बी.पी.एल. परिवारों को केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है।

10. मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन गत 14 जनवरी से 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये मासिक की गई।

11. छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए 'हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना-2025' गत 23 जनवरी को शुरू की गई। इसमें जी.एस.टी. से पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान किया जा रहा है।इसके तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।

12. 70 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी बुजुर्गों के लिए 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत 5 लाख रुपये सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की गई।

13. राज्य में बी.पी.एल. परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों की मोतियाबिंद सर्जरी मुफ्त की जा रही है।

14. 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' में माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर की दर्शन यात्रा को भी शामिल किया गया।इसके अलावा प्रयागराज में हुए महाकुम्भ की यात्रा को भी शामिल किया गया।

15. नागरिक कल्याण हेतु गत 22 अक्तूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू किए गए।इनमें 75 हजार से अधिक शिकायतों का समाधान किया किया गया।इसके अतिरिक्त, जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से भी आमजन की

45 हजार से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया।

16. हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण का गठन किया गया।

17. नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां प्रतिवर्ष 20 से बढ़ाकर 25 कीं।हरियाणा कौशल रोजगार निगम में काम कर रही महिला कर्मियों की छुट्टियां प्रतिवर्ष 10 से बढ़ाकर 22 कीं।

18. नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून लागू किया।

19. हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी।जिसके तहत उप-पोर्टल का प्रावधान किया है।

20. नई एकीकृत पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए 2 जुलाई, 2025 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।इससे हरियाणा के 2 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।

21. डंकी रूट की समस्या को खत्म करने हेतु 26 मार्च, 2025 को विधानसभा में बिल पास करके एक्ट बनाया गया। इसका उद्देश्य यात्रा एजेंटों के काम में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना है।साथ ही उनके अवैध और धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन की जांच कर उन पर अंकुश लगाना है।

22. साइबर सुरक्षा में सुधार और साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रत्येक उपमंडल में साइबर डैस्क / सैल की स्थापना की जा चुकी है।

23. जिला सिरसा, फतेहाबाद, अम्बाला, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल एवं पानीपत में 8 डैडिकेटिड एन.डी.पी.एस. फास्ट ट्रैक कोर्ट की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। एच.एस.एन.सी.बी. द्वारा एन.डी.पी.एस. मानिटरिंग सेल स्थापित की गई है।

24. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों के लिए 12 दिसम्बर, 2024 को अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत गांव का कोई निवासी जिसने 31.03.2004 को या उससे पहले 500 वर्ग गज तक की भूमि पर अपना घर बनाया है, वह 31.03.2004 के कलेक्टर रेट के आधे मूल्य पर उस भूमि को खरीदने बारे आवेदन कर सकता है।

25. रेवाड़ी में सैनिक संग्राहलय पहले से ही स्थापित है और इसके नवीनीकरण के लिए 18 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

26. हरियाणा में एम.एस.एम.ई. निदेशालय ने प्राकृतिक आपदाओं और आग तथा चोरी जैसी अप्रत्याशित घटनाओं की बीमा कवरेज के लिए वित्तीय सब्सिडी प्रदान करता है।सुरक्षा ऑडिट पर किए गए व्यय के 75 प्रतिशत, अधिकतम 1 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाती है।

27. शहीद सैनिकों के हर बच्चे को 6 वीं से 12वीं कक्षा तक 60,000 रुपये, स्नातक तक 72,000 रुपये तथा स्नातकोत्तर तक 96,000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति मिल चुकी है।

28. किसानों / उद्यमियों के लिए 5000 मीट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतू विभागीय स्कीमों में 35 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है, जोकि 1.68 करोड़ रुपये से 2.10 करोड़ रुपये प्रति लाभार्थी है।हर जिले का किसान/उद्यमी के लिए उपरोक्त अनुदान सुविधा उपलब्ध है।

29. मौसमी फसलों के लिए जलवायु अनुकूल फसल किस्में उपलब्ध कराना एक निरन्तर प्रक्रिया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इस विषय पर कार्य कर रहा है।पिछले 4 वर्षों में विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों की 44 किस्में अनुमोदित की है।चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इस कार्य में केन्द्र सरकार का सहयोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के माध्यम से प्राप्त करता है।

30. हरियाणा राज्य में हल्दी, लहसुन व अदरक के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है। अन्य मसालों की खेती जैसे धनिया, मेथी आदि के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

31. 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना' के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा पाले जा रहे 100 छोटे पशुओं (भेड़, बकरी) व 50 सूकर का बीमा मुफ्त किया जा रहा है।

32. राज्य में वर्ष 2018 से 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना' चलाई जा रही है, जिसमें एक पशुपालक के 10 बड़े व 100 छोटे पशुओं के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक बीमा का कवर केवल 15 प्रतिशत प्रति पशु प्रतिवर्ष प्रीमियम पर किया जा रहा है।

33. बाजरा जैसे श्री अन्न फसलों की ब्रांडिंग और प्रमोशन को प्राथमिकता के लिए हैफेड ने एक महिला स्वयं सहायता समूह के साथ गठजोड़ किया है और हैफेड की ब्रांडिंग में बाजरा जीरा बिस्कुट, ज्वार तिल बिस्कुट, भुना हुआ ज्वार नमकीन तथा भुना हुआ बाजरा नमकीन लॉन्च किया है।

34. सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मासिक राशि को मंहगाई सूचकांक 2016 की दर से अधिक 01.01.2016 से 1600 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह की जा चुकी है।

35. दिव्यांग कर्मचारियों / स्व-रोजगार चलाने वाले व्यक्ति या संस्था को प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। राज्य पुरस्कार की राशि 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक है।

36. हर जिले में अलग-अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाने हेतु विभागीय स्तर पर कार्यवाही कर दी गई है। खेल नर्सरियों की हिदायतों अनुसार ओलम्पिक / कॉमनवेल्थ / एशियन खेलों की ही नर्सरियां खोली गई है।

37. 'हरियाणा सरकार प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2.0' के तहत प्रशिक्षुओं की वजीफा/छात्रवृति राशि 1500 रुपये प्रतिमाह सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

38. राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु सरकार द्वारा हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप क, ख, तथा ग) सेवा नियम-2021 बनाये गये है।इनके तहत पदक विजेता खिलाडियों को योग्यता अनुसार नौकरी प्रदान की जा रही है।

39. महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' को लागू करने का निर्णय लिया गया है।यह योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जयंती, 25 सितंबर, 2025 से की गई।इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

40. सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के अतिरिक्त, 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। यह सुविधा 1 अप्रैल, 2025 से लागू की जा चुकी हैं।

41. दिव्यांग युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

42. बरवाला औद्योगिक एस्टेट, पंचकुला के विकास के पहले चरण का कार्य पूर्ण।दूसरे चरण का कार्य जारी।

43. सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों को डिजिटल लाइब्रेरी सदस्यता प्रदान करेंगे। इसके तहत 26 कॉलेजों ने ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया की और 149 कॉलेजों ने भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की सदस्यता ली है।

44. जींद जिले में 2 राज्य स्तरीय हर्बल पार्क / उद्यान (16 और 20 एकड़) और रेवाड़ी जिले में 13 राज्य स्तरीय हर्बल पार्क स्थापित किये जा चुके हैं।

45. हिसार हवाई अड्डे से 14 अप्रैल, 2025 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हिसार से अयोध्या की फ्लाईट को हरी झंडी दी गई है। 9 जून, 2025 को हिसार से चंडीगढ़ और 11 सितम्बर, 2025 को हिसार से जयपुर की फ्लाईट का संचालन किया जा चुका है। जल्द ही जम्मू व अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। अंबाला हवाई अड्डे के सभी सिविल कार्य पूरे हो चुके है। एयरपोर्ट फ्लाईट संचालन हेतु तैयार है। वाणिज्यिक घरेलू उड़ान संचालन शीर्घ ही शुरू होगा।

46. मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए राज्य भर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एन.सी. डी. क्लिनिक स्थापित करने के प्रस्ताव को अधिकारियों द्वारा मंजूरी मिल गई है। 1 मई, 2025 से राज्य के सभी पी.एच.सी. में एन.सी.डी. क्लिनिक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

46 संकल्प सिद्ध

1. नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 24,000 युवाओं को ग्रुप सी की सरकारी नौकरियां दी।
2. सभी जिला सरकारी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवा शुरू।
3. 25-दिवसीय शिकायत समाधान ढांचा स्थापित और सभी सरकारी विभागों में नागरिक शिकायतों पर पारदर्शिता सुनिश्चित ।
4. 2804 आंगनवाड़ियों को 'सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदला जा रहा है। वर्ष 2029 तक 10,000 आंगनवाड़ियों को 'सक्षम आंगनवाड़ी' केंद्रों में बदला जाएगा।
5. किसानों को 48 घंटे के भीतर डी.बी.टी. के माध्यम से फसल खरीद का भुगतान ।
6. ई-खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे गेट पास बनाने की सुविधा।
7. आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख तक के मुफ्त ईलाज की सुविधा ।
8. अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश, 2024 की तर्ज पर शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक की गेस्ट फैकल्टी जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए कानून।
9. खेल, रंगमंच, कला और संस्कृति के क्षेत्र में सफल दिव्यांगों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर 50,000 रुपये तक नकद पुरस्कार ।
10. हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया।
11. सभी 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (टरढ) पर खरीद ।
12. शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सी.सी.टी.वी कवरेज का विस्तार कर लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाई गई।
13. मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये की।
14. ग्रामीण क्षेत्र में 500 वर्ग गज तक की भूमि पर पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से रिहायशी मकान बना कर रह रहे सभी परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दिया।
15. सभी सरकारी कॉलेजों को डिजिटल लाइब्रेरी सदस्यता दी गई।
16. सभी जिलों को शामिल करने के लिए अमृत सरोवर पहल के तहत काम का विस्तार तेजी लाने के कदम उठाए।
17. नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून लागू।
18. जींद व रेवाडी में आयष हर्बल पार्क स्थापित।
19. रेवाड़ी में सैन्य संग्रहालय स्थापित।
20. राज्य में हल्दी के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ तथा धनिया के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है।
21. राज्य के छोटे व्यापारियों को जी.एस.टी. से पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाये का निपटान करने के लिए एकमुश्त ब्याज व जुमार्ना राहत स्कीम लागू।
22. सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के अतिरिक्त, 25 लाख रुपये के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार देगी।
23. डंकी रूट की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कानून लागू।
24. यमुनानगर में 800 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई।
25. हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू।
26. सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और केंद्रीकृत एन.डी.पी.एस. मॉनिटरिंग सेल स्थापित।
27. हरियाणा के हर पुलिस उपमंडल में एक साइबर पुलिस सेल स्थापित।
28. मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गैर-संचारी रोग क्लीनिक स्थापित।
29. 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में वैष्णो देवी और शिरडी जैसे अतिरिक्त तीर्थ स्थलों को शामिल किया।
30. शहीद सैनिकों के बच्चों को 6वीं से 12वीं कक्षा तक 60,000 रुपये, स्नातक तक 72,000 रुपये तथा स्नातकोत्तर तक 96,000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का प्रावधान।
31. महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके मनचाहे दिन पर मासिक छुट्टी का प्रावधान।
32. हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना लागू।
33. हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना शुरू।
34. ग्रुप-सी के पदों के लिए लगभग 13.50 लाख युवाओं ने सी.ई.टी. परीक्षा दी ।
35. पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत प्रति पशु 15% प्रतिवर्ष प्रीमियम पर बीमा।
36. पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति परिवारों द्वारा पाले गए भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों का बीमा मुफ्त किया जा रहा है।
37. हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी।
38. खिलाड़ियों को 500 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।
39. सड़क उत्थान परियोजना' शुरू, लगभग 4827 करोड़ रुपये से 9410 किलोमीटर लम्बी 4227 सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर।
40. हरियाणा के ब्लॉकों में 390 इंडोर जिम की स्थापना की गई।
41. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता।
42. हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय तथा बी.पी.एल. परिवारों को केवल 500 रुपये में एल.पी.जी. सिलेंडर दिया जा रहा है।
43. हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण गठित ।
44. खो-खो और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को खेल महाकुम्भ में शामिल कर प्रतियोगिता करवाई गई।
45. निरोगी हरियाणा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जाँच की जा रही है।
46. 48 कोस कुरुक्षेत्र में आने वाले सभी 182 महाभारत, पितृ मोक्ष, शिव, शक्ति और अन्य प्राचीन तीर्थ स्थलों पर विकास कार्य प्रगति पर और तीर्थाटन को बढ़ाने के लिए 2 परिक्रमा बस सर्विस शुरू ।

गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रमों में विभाजन की कोशिशों पर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका ने जताई गहरी चिंता

संवाददाता
नई दिल्ली

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका ने नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस (शहीदी पुर्ब) को सामूहिक रूप से मनाए जाने वाले कार्यक्रमों में विभाजन पैदा करने की कोशिशों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री अमृतसर साहिब की ओर से इस वर्ष की शुरूआत से ही देशव्यापी धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जो नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। लेकिन यह दुःख की बात है कि सरदार परमजीत सिंह सरना ने दिल्ली में अलग से कार्यक्रम आयोजित करने शुरू कर दिए हैं – वही विभाजनकारी परंपराएँ दोहराई जा रही हैं, जो उनके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष काल में भी देखने को मिली थीं – जब वे एक ही गुरुपर्व दो-दो तिथियों पर मनाते थे और संगत में भ्रम की स्थिति पैदा करते थे।

सरदार कालका ने बताया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से डूबरी साहिब से आरंभ किया गया नगर कीर्तन अपनी यात्रा के दौरान दिल्ली पहुँचने वाला था। लेकिन सरदार सरना ने बिना शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष या दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से परामर्श किए, दिल्ली में अलग से आयोजन शुरू कर दिए हैं, जिससे कार्यक्रमों की एकता प्रभावित हो रही है।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले सप्ताह से ही दिल्ली में नगर कीर्तन और अन्य कार्यक्रमों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं – जैसे कि 24 अक्टूबर को गुरुद्वारा नानक पिओ साहिब और 25 अक्टूबर को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में – परंतु शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या कार्यक्रम आयोजकों की ओर से दिल्ली कमेटी को किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना, आवास या प्रबंध सहयोग का अनुरोध हाल ही में ही प्राप्त हुआ है।

सरदार कालका ने कहा कि उन्होंने स्वयं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरजिंदर सिंह धामी से संपर्क किया, जिन्होंने बाद में सभी प्रबंधों की जानकारी साझा की और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सहयोगी भूमिका की सराहना की।

हालांकि, सरदार कालका ने 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली में होने वाले महत्वपूर्ण सेमिनार ह्लगुरु तेग बहादुर झ्र हिंद की चादरह्व के स्थल की चयन पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह स्थान प्रायः ऐसे आयोजनों के लिए प्रयोग होता है जहाँ शराब और मांसाहारी भोजन परोसा जाता है, जो एक पवित्र धार्मिक आयोजन के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष धामी से तुरंत इस स्थल की चयन पर पुनर्विचार करने की अपील की।

सरदार कालका ने जोर देकर कहा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास कई उपयुक्त धार्मिक और शैक्षणिक स्थल हैं – जैसे कि खालसा कॉलेज और गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ऑडिटोरियम – जहाँ यह आयोजन श्रद्धा और सम्मान के साथ बिना किसी खर्चे के आयोजित किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की दिल्ली सहयोगी टीम में भी अंतरकलह है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह जी.के. ने भी इंडिया हैबिटैट सेंटर के चयन का विरोध किया था, लेकिन उसे रोक नहीं सके। कालका ने कहा, ह्लसिर्फ विरोध करना पर्याप्त नहीं था, आपका कर्तव्य था कि गुरु साहिब का शहीदी गुरुपर्व उस स्थान पर न मनाया जाए जहाँ शराब का सेवन होता हो।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी चिंता जताई कि शिरोमणि अकाली दल (रअऊ) के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल – जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में संवैधानिक रूप से किसी आधिकारिक पद पर नहीं हैं – को सेमिनार का मुख्य वक्ता बताया गया है, जबकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष धामी का नाम बाद में लिखा गया है।उन्होंने पूछा, ह्लक्या अब राजनीतिक व्यक्तियों को अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से भी ऊपर रखा जा रहा है?

अंत में, सरदार कालका ने पुनः शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरजिंदर सिंह धामी से अपील की कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी पुर्ब की पवित्रता बनाए रखते हुए, सेमिनार का स्थल इंडिया हैबिटैट सेंटर से बदलकर किसी उपयुक्त धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान में रखा जाए। उन्होंने कहा, ह्लहमारा उद्देश्य एकता और श्रद्धा है, विभाजन नहीं। आओ हम गुरु साहिब की पवित्र याद को विनम्रता और सामूहिक सम्मान के साथ मना कर सच्ची सेवा का प्रतीक बनें।

आपकी पूंजी -आपका अधिकार

कपूरथला में अन क्लेमड एसेट्स के तवरित निपटान हेतु जन जागरण शिविर का आयोजन

संवाददाता
कपूरथला/चंडीगढ़

16 अक्टूबर 2025 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति पंजाब के नेत्रत्व में पंजाब के कपूरथला जिले में विशाल शिविर का आयोजन किया गयो पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक रामकिशोर मीना द्वारा बताया गया कि अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा सभी वित्तीय संस्थाओ से संपर्क करते हुए भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेर्शानुसार एक विशाल शिविर का आयोजन किया जिसमे बैंक, बीमा ,पेंशन एवं म्युचुअल फंड विभागों के शीर्ष अधिकारियो द्वारा भाग लिया गयो उन्होंने आगे बताया की बैंक में जमा राशि को यदि 10 वर्ष तक भी प्राप्त नहीं किया गया हो तो जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक को चली जाती हैं इस दावा रहित पुरानी जमा राशि, म्युचुअल फंड, बीमा राशि, को कैसे प्राप्त किया जा सकता, इसकी विस्तृत जानकारी दी गयी इस तरह के जागरूकता शिविर सभी राज्यों में लगाये जा रहे है ताकि पुरानी दावा रहित जमा राशी को वापस उसके असली मालिक को या नामित व्यक्ति को या कानूनन उतराधिकारी उत्तराधिकारियों को वापस की जा सके ।वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आपकी पूंजी -आपका अधिकार जन जागरण अभियान 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक चलाया गया है आगामी दिनों में प्रत्येक जिले में जागरूकता शिवर आयोजित किये जायेंगे. अधिक जानकारी हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के उदगम पोर्टल एवं अपनी नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते है।

खुशी, देखभाल और सुरक्षा के साथ दिवाली मनाएं: पीजीआईएमईआर

संवाददाता
चंडीगढ़

दीपावली, रोशनी का त्योहार, सभी के लिए खुशियाँ और एकजुटता लाता है। इसे मनाने की तैयारी करते हुए, आइए हम इसे ज़िम्मेदारी से करें - अपनी, अपने परिवार और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए।

पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ का प्लास्टिक सर्जरी विभाग सभी को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल दिवाली के लिए निम्नलिखित सावधानियों का पालन करने की सलाह देता है:

*दीये, मोमबत्तियाँ या पटाखे जलाते समय ढीले या सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें।

*पटाखे और दीये जलाते समय एक हाथ की दूरी बनाए रखें।

*ऐसे पटाखे कभी न उठाएँ जो फटे न हों, क्योंकि इनसे हाथ और चेहरे पर गंभीर चोट लग सकती है।

*इस्तेमाल किए गए पटाखों को पानी या रेत से भरी बाल्टी में डुबोकर सुरक्षित रूप से फेंक दें।

* अपने पैरों की सुरक्षा के लिए पटाखे जलाते समय जूते पहनें।

*पटाखे हाथ में लेकर न फोड़ें।ऐसा अक्सर बहादुरी या ₹कूलर₹ व्यवहार दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह बेहद खतरनाक है।

हर साल, विभाग में ऐसे असुरक्षित तरीकों के कारण गंभीर हाथ की चोटों वाले कई मरीज आते हैं।इनमें से कई के परिणामस्वरूप गहरी जलन, उंगली का कटना और हाथ की कार्यक्षमता का स्थायी नुकसान होता है। ये और अन्य जलने की चोटें हैं:

* केवल हरे पटाखे इस्तेमाल करें और अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करें।

अगर जलन हो जाए:

*जले हुए हिस्से पर तुरंत साफ, ठंडा पानी डालें जब तक जलन बंद न हो जाए।

* टूथपेस्ट, स्याही, मक्खन या कोई भी घरेलू पदार्थ न लगाएँ।

*सूजन शुरू होने से पहले अंगूठियाँ, चूड़ियाँ या टाइट एक्सेसरीज उतार दें।

* अगर कपड़ों में आग लग जाए, तो नियम याद रखें: रुकें, गिरें और लुढ़कें।

आग को फैलने से रोकने के लिए हिलना-डुलना बंद कर दें। आग को अपने चेहरे तक पहुँचने से बचाने के लिए जमीन पर गिर जाएँ। आग को बुझाने के लिए जमीन पर लुढ़कें।

ईएसटीआईसी2025 का शुभारंभ समारोह और बीआरआईसीएनएबीआई, मोहाली में डिईएसआईजीएन फॉर बायोई3 प्रतियोगिता का उद्घाटन

संवाददाता
मोहाली

बी.आर.आई.सी.राष्ट्रीय कृषिखाद्य एवं जैवनिर्माण संस्थान (बी.आर.आई.सी.एन.ए.बी.आई.) ने उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन (ई.एस.टी.आई.सी.2025) का शुभारंभ समारोह आयोजित किया और इसी अवसर पर डि.ई.एस.आई.जी.एन. फॉर बायोई3 प्रतियोगिता की शुरूआत की।

ई.एस.टी.आई.सी.2025 का उद्देश्य भारत एवं विदेशों के वैज्ञानिकों, नवप्रवर्तकों, नीतिनिमार्ताओं और विशेषज्ञों को एक साझा मंच पर लाना है, ताकि वे नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर विचारविमर्श कर सकें और सामूहिक सहयोग से समाधान विकसित करें। यह सम्मेलन 3 से 5 नवम्बर, 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। इसमें प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के मार्गदर्शन में 13 मंत्रालय और विभाग सहभागिता करेंगे। सम्मेलन में भारत की विभिन्न उपलब्धियों को 11 प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाएगा, जिनमें जैवनिर्माण क्षेत्र का नेतृत्व जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) एवं बी.आर.आई.सी.एन.ए.बी.आई. द्वारा किया जाएगा। विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप, ई.एस.टी.आई.सी. ऐसे

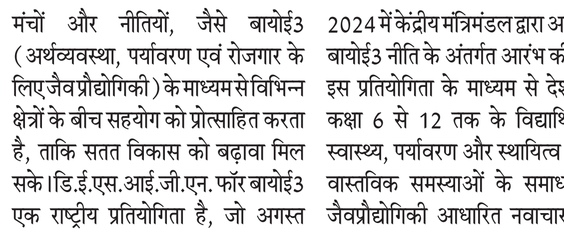

मंचों और नीतियों, जैसे बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है, ताकि सतत विकास को बढ़ावा मिल सके। डि.ई.एस.आई.जी.एन. फॉर बायोई3 एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जो अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बायोई3 नीति के अंतर्गत आरंभ की गई है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से देशभर के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्थायित्व से जुड़ी वास्तविक समस्याओं के समाधान हेतु जैवप्रौद्योगिकी आधारित नवाचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपने संबोधन में प्रो. राजेश गोखले ने युवाओं को नवाचारपूर्ण विचारों के साथ इन कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित किया ताकि वे राष्ट्रनिर्माण में योगदान दे सकें। वहीं श्री प्रियांक भारती ने युवाओं से इन पहलों में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आान किया। समारोह का समापन विशिष्ट अतिथियों के प्रेरक संबोधन के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने जैवप्रौद्योगिकी एवं युवा नवाचार की भूमिका को स्थायी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम का समापन धन्यवादप्रस्ताव और राष्ट्रगान के साथ हुआ।